Website : www.mantrabharat.com

जुनून है सच लिखने का

E-Mail : mantrabharatmumbai@gmail.com, Mo. 7007837917

संस्करण : मुंबई
वर्ष : 11
अंक : 65
पृष्ठ : 8
मूल्य : 2.0
शुक्रवार, 13 मार्च, 2026

मंत्र भारत

हिन्दी दैनिक

मुंबई, लखनऊ, प्रयागराज एवं ग्वालियर से एक साथ प्रकाशित एवं ठाणे, नवी मुम्बई, पालघर, नासिक एवं पुणे से प्रसारित

3 राज्यभर में नियंत्रण कक्ष स्थापित, ...

4 मुहम्मद यूनुस दौर के बाद बदली बांग्लादेश ...

7 टी20 वर्ल्ड कप से पहले पिता के निधन ...

संक्षिप्त न्यूज

पेट्रोलियम मंत्रालय का बयानः देश के किसी भी पेट्रोल पंप पर तेल खत्म नहीं, घबराने की जरूरत नहीं

नई दिल्ली : पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और होर्मुज जलडमरूमध्य के लगभग बंद होने की खबरों के बीच भारत में पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस की आपूर्ति को लेकर सरकार ने स्थिति स्पष्ट की है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि देश में कच्चे तेल की उपलब्धता सामान्य है और किसी भी पेट्रोल पंप पर ईंधन खत्म होने की स्थिति नहीं है।

मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि भारत में कच्चे तेल की आपूर्ति फिलहाल आरामदायक स्थिति में है और देशभर के लगभग एक लाख पेट्रोल पंपों में कहीं भी तेल खत्म होने की सूचना नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि देश में रोजाना लगभग 55 लाख बैरल कच्चे तेल की खपत होती है और भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तेल परिशोधन करने वाला देश है। इसलिए पेट्रोल और डीजल जैसे उत्पादों की उपलब्धता को लेकर चिंता की कोई बात नहीं है।

एलपीजी की उपलब्धता को लेकर भी सरकार ने कई कदम उठाए हैं। नौ मार्च को आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत आदेश जारी कर सभी रिफाइनरियों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद घरेलू उत्पादन लगभग 25 प्रतिशत से बढ़कर करीब 28 प्रतिशत तक पहुंच गया है।

मंत्रालय के अनुसार भारत अपनी एलपीजी जरूरत का लगभग 60 प्रतिशत आयात करता है, जिसमें से करीब 90 प्रतिशत आपूर्ति होर्मुज जलडमरूमध्य के रास्ते आती है। मौजूदा परिस्थितियों में यह चुनौतीपूर्ण जरूर है, लेकिन सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि देश में गैस की आपूर्ति प्रभावित न हो।

सुजाता शर्मा ने बताया कि देश में प्रतिदिन लगभग 50 लाख एलपीजी सिलिंडर की डिलीवरी की जाती है।

एलपीजी सिलेंडर को लेकर सियासत तेज

पीएम ने कहा- अफवाह फैलाने वालों पर नजर रखो, जमाखोरी करने वाले जाएंगे जेल

नई दिल्ली। देश में एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति को लेकर उठी आशंकाओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थिति पर कड़ा रुख अपनाते हुए केंद्रीय मंत्रियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि किसी भी तरह के दुष्प्रचार और घबराहट फैलाने की कोशिशों का आक्रामक तरीके से जवाब दिया जाए। मोदी सरकार ने साफ किया है कि देश में घरेलू रसोई गैस की आपूर्ति को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है और किसी भी संकट से निपटने के लिए व्यापक तैयारियां पहले से मौजूद हैं।

सूत्रों के अनुसार मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री ने मंत्रियों से कहा कि कुछ लोग एलपीजी आपूर्ति की स्थिति को लेकर अनावश्यक घबराहट पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मंत्रियों को निर्देश दिया कि ऐसी हर कोशिश पर कड़ी नजर रखी जाए और तथ्यों के साथ उसका तुरंत जवाब दिया जाए। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया सहित हर मंच पर विपक्ष के दुष्प्रचार का आक्रामक तरीके से जवाब दिया जाना चाहिए।

प्रधानमंत्री का कहना था कि मौजूदा स्थिति किसी एक देश तक सीमित नहीं है बल्कि वैश्विक परिस्थितियों के कारण दुनिया के कई देशों को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके बावजूद भारत की तैयारियां मजबूत हैं और सरकार किसी भी तरह की आपूर्ति बाधा से निपटने में पूरी तरह सक्षम है। सरकार का जोर इस बात पर है कि घरेलू उपभोक्ताओं को रसोई गैस की उपलब्धता में किसी प्रकार की समस्या न होने दी जाए।

इसी बीच, केंद्र सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर भी सख्त कदम उठाए हैं। गृह सचिव गोविंद मोहन ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों तथा पुलिस महानिदेशकों के साथ विस्तृत बैठक कर देशभर में एलपीजी की उपलब्धता और आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा की। लगभग दो घंटे चली इस बैठक में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया।

बैठक में राज्यों को निर्देश दिया गया कि एलपीजी से जुड़ी पूरी आपूर्ति श्रृंखला पर कड़ी निगरानी रखी जाए। इसमें बोटलिंग प्लांट, वितरण नेटवर्क और परिवहन व्यवस्था की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया है। अधिकारियों को यह भी कहा गया है कि स्थानीय स्तर पर रोजाना एलपीजी की उपलब्धता की समीक्षा करें और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या कालाबाजारी की कोशिशों पर तुरंत कड़ी कार्रवाई करें।

सूत्रों के अनुसार रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल इकाइयों को भी एलपीजी उत्पादन अधिकतम करने और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए आपूर्ति को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने होटल और रेस्तरां जैसे वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को दी जाने वाली एलपीजी आपूर्ति पर कुछ नियंत्रण लगाए हैं, ताकि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पर्याप्त गैस उपलब्ध रह सके। हालांकि अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों जैसी आवश्यक सेवाओं पर ये प्रतिबंध लागू नहीं होंगे।

इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने चौबीस घंटे संचालित होने वाले अपने नियंत्रण कक्ष को और मजबूत किया है। इसमें सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा पेट्रोलियम मंत्रालय के नोडल अधिकारियों को भी शामिल किया गया है, ताकि राज्यों के साथ बेहतर समन्वय, तथ्य जांच और वास्तविक समय में स्थिति स्पष्ट करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।

टीएमसी प्रतिनिधिमंडल को राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात का नहीं मिला समय, फिर लिखा पत्र

नई दिल्ली। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसदों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के लिए समय मांगा था, ताकि वे पश्चिम बंगाल सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में उन्हें जानकारी दे सकें। लेकिन राष्ट्रपति भवन ने 'समय की कमी' का हवाला देते हुए उनके मिलने के अनुरोध खारिज कर दिया। एक सूत्र ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

यह विवाद उस समय बढ़ा, जब शनिवार को राष्ट्रपति ने यह देखकर नाराजगी जताई कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी या उनके कोई मंत्री बागडोगरा हवाई अड्डे पर उनका स्वागत करने नहीं पहुंचे। राष्ट्रपति मुर्मू एक अंतरराष्ट्रीय आदिवासी सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंची थीं। इस घटना ने राजनीतिक बहस छेड़ दी।

किसने लिखा था राष्ट्रपति को पत्र?

सूत्रों के मुताबिक, टीएमसी के एक वरिष्ठ टीएमसी नेता ने नौ मार्च को राष्ट्रपति मुर्मू को पत्र लिखा था, जिसमें 12 से 15 सदस्यीय पार्टी प्रतिनिधिमंडल को मुलाकात के लिए समय मांगा गया था। इनस प्रतिनिधिमंडल में सांसद और राज्य मंत्री शामिल थे।

मुलाकात का मकसद क्या था?

पत्र में कहा गया कि प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति को पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से सभी वर्गों के समावेशी विकास के लिए उठाए गए कल्याणकारी कदमों के बारे में जानकारी देना चाहता है। हालांकि, यह अनुरोध खारिज कर दिया गया।

राष्ट्रपति भवन ने क्या जवाब दिया?

राष्ट्रपति भवन ने टीएमसी को सूचित किया कि उनका अनुरोध देखा गया, लेकिन 'समय की कमी' के कारण इसे पूरा नहीं किया जा सका। सूत्र ने कहा कि टीएमसी ने फिर से राष्ट्रपति कार्यालय को पत्र लिखा है और अगले सप्ताह मिलने का समय मांगा है।

सम्मेलन में कम उपस्थिति पर राष्ट्रपति की नाराजगी

राजनीतिक विवाद उस समय और बढ़ गया, जब शनिवार को राष्ट्रपति ने संत समाज के सम्मेलन में कम उपस्थिति पर अपनी असंतोष जताया। उन्होंने राज्य सरकार के निर्णय पर सवाल उठाया कि सम्मेलन स्थल को विधाननगर से बागडोगरा हवाई अड्डे के पास क्यों स्थानांतरित किया गया। उन्होंने पूछा कि क्या प्रशासन ने सोचा था कि कोई भी इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होगा।

तेजस्वी प्रसाद यादव का नीतीश सरकार पर आंकड़ों से वार, कहा- बिहार हर विकास सूचकांकों में फेल

पटना **(एजेंसी)**। राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने गुरुवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि उनके शासनकाल में राज्य ने सभी विकास सूचकांकों पर सबसे खराब प्रदर्शन किया है। तेजस्वी का यह हमला ऐसे समय में आया है जब नीतीश कुमार अपनी 'समृद्धि यात्रा' पर हैं और आरजेडी के शासनकाल के 'जंगल राज' के विपरीत अपने शासनकाल में हुए बिहार के विकास की बात कर रहे हैं। नीतीश और उनकी सरकार पर हमला करते हुए तेजस्वी ने 'X' पर लिखा कि बिहार एक अनूठा और अद्वितीय राज्य है जहां एनडीए की दो इंजन वाली सरकार दशकों से सत्ता में है, फिर भी यह देश का सबसे गरीब राज्य है, जहां देश में सबसे अधिक पलायन, सबसे अधिक अपराध, सबसे अधिक भ्रष्टाचार, सबसे अधिक बेरोजगारी, सबसे अधिक बहुआयामी गरीबी और साथ ही देश में सबसे अधिक स्कूली शिक्षा छोड़ने की दर है।

उन्होंने आगे कहा कि दूसरी ओर, बिहार में देश में सबसे कम साक्षरता दर, सबसे कम प्रति व्यक्ति आय, सबसे कम किसानों की आय, सबसे कम प्रति व्यक्ति निवेश, सबसे कम प्रति व्यक्ति उपभोग, सबसे कम कंप्यूटर साक्षरता, सबसे कम बिजली की खपत, सबसे कम बुनियादी ढांचा, सबसे कम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सबसे कम औद्योगिक इकाइयां और स्कूलों में कंप्यूटर और आईसीटी प्रयोगशालाओं की सबसे कम संख्या है।

लोकसभा में लौटे स्पीकर ओम बिरला का विपक्ष को कड़ा संदेश

किसी को विशेषाधिकार नहीं, नियमों से चलेगा सदन

नई दिल्ली। विपक्ष द्वारा उनके खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को खारिज किए जाने के एक दिन बाद, ओम बिरला आज लोकसभा में अध्यक्ष की कुर्सी पर वापस लौटे। विपक्ष द्वारा उन पर लगाए गए पक्षपात के आरोपों को खारिज करते हुए बिरला ने कहा कि कुछ लोगों ने मुझ पर कुछ सांसदों को संसद में बोलने से रोकने का आरोप लगाया है। लेकिन मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं हमेशा सभी सांसदों को बोलने की अनुमति देता हूं, लेकिन नियमों और विनियमों के तहत।

अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में कहा कि मैंने हमेशा यह प्रयास किया है कि लोकसभा में प्रत्येक सदस्य नियमों के अनुसार अपने विचार रखें, इसके लिए सभी को समय देने का प्रयास किया है। मैंने हमेशा यह प्रयास किया कि सदन की कार्यवाही निष्पक्षता, अनुशासन, संतुलन और नियमों के साथ संचालित हो।

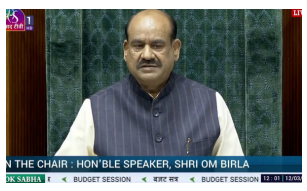

उन्होंने कहा कि मैंने अपने नैतिक कर्तव्य का पालन करते हुए अपने खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिए जाने के साथ ही लोकसभा की कार्यवाही के संचालन से खुद को अलग कर लिया। इसके साथ ही बिरला ने कहा कि सदन द्वारा मुझ पर व्यक्त किए गए विश्वास के लिए सभी का आभार व्यक्त करता हूं, इस विश्वास को अपनी जिम्मेदारी मानते हुए पूरी निष्ठा, निष्पक्षता और संवैधानिक मर्यादा के साथ निभाऊंगा।

उन्होंने कहा कि कुछ सदस्यों का मानना था कि नेता प्रतिपक्ष सदन से ऊपर हैं और किसी भी विषय पर बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा विशेषाधिकार किसी को नहीं है और चाहे प्रधानमंत्री हों, मंत्री हों, विपक्ष के नेता हों या अन्य सदस्य, सभी को नियम के अनुसार ही बोलने का अधिकार है। ये नियम सदन ने ही बनाए हैं और मुझे विरासत में मिले हैं।

ओम बिरला ने कहा कि स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में तीसरी बार लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुई है। मैंने हमेशा यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि सदन का प्रत्येक सदस्य नियमों और प्रक्रियाओं के दायरे में रहकर मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करे। हालांकि, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को एलपीजी के मुद्दे पर बोलने देने की मांग करते हुए कांग्रेस सदस्यों ने शोर-शराबा किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।

यूएस-ईरान युद्ध पर राहुल गांधी की बड़ी चेतावनी, बोले- ये तो सिर्फ शुरुआत है, असली दर्द बाकी है

नई दिल्ली। लोकसभा में बोलते हुए राहुल गांधी ने चेतावनी दी कि होर्मुज जलडमरूमध्य में किसी भी प्रकार की रुकावट या बंद होने से भारत की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा आपूर्ति सीधे तौर पर प्रभावित होगी। उन्होंने कहा कि एलपीजी की उपलब्धता को लेकर चिंता पहले से ही फैल रही है और संघर्ष बढ़ने पर यह और भी गंभीर हो सकती है। ऊर्जा सुरक्षा को किसी भी देश के लिए मूलभूत बताते हुए गांधी ने यह भी सवाल उठाया कि भारत को अमेरिका को इस बात पर प्रभाव डालने की अनुमति क्यों देनी चाहिए कि वह गैस कहां से खरीदे।

राहुल गांधी ने कहा कि मध्य पूर्व में युद्ध छिड़ गया है। अमेरिका, इज़राइल और ईरान आपस में लड़ रहे हैं। इस युद्ध के दूरगामी परिणाम होंगे। होर्मुज जलडमरूमध्य, जिससे वैश्विक तेल का 20इ प्रवाह होता है, बंद कर दिया गया है। इसके बहुत गंभीर परिणाम होंगे, खासकर हमारे लिए, क्योंकि हमारे तेल और प्राकृतिक गैस का एक बड़ा हिस्सा होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर गुजरता है। अभी तो बस शुरुआत हुई है। रेस्तरां बंद हो रहे हैं। एलपीजी को लेकर व्यापक दहशत फैली हुई है... यह तो बस शुरुआत है।

गांधी ने आगे कहा कि हर राष्ट्र की नींव उसकी ऊर्जा सुरक्षा है। अमेरिका को यह तय करने देना कि हम किससे तेल खरीदें, किससे गैस खरीदें और क्या हम रूस से तेल खरीद सकते हैं या नहीं...विभिन्न तेल आपूर्तिकर्ताओं के साथ हमारे संबंध हम खुद तय कर सकते हैं। यही सौदा हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत जैसा राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र को, किसी दूसरे राष्ट्र के राष्ट्रपति को, हमें रूसी तेल खरीदने की अनुमति देने या यह तय करने की अनुमति क्यों देगा कि हमारे संबंध किसके साथ हों।

राहुल गांधी ने केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी पर तंज कतसे हुए कहा कि मैंने पहेली सुलझा ली है और पहेली समझौते से जुड़ी है। हमारे सामने यहां एक सज्जन बैठे हैं जो तेल मंत्री हैं। उन्होंने खुद कहा है कि वे श्री एपस्टीन के मित्र हैं।

टीटीवी दिनाकरन का बड़ा दावाः

तमिलनाडु में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की बनेगी सरकार, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के खिलाफ होगी 'मौन क्रांति'

चेन्नई। अमर मक्कल मुनेत्र कड़गम के महासचिव टीटीवी दिनाकरन ने दावा किया है कि तमिलनाडु में आगामी चुनावों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता वर्तमान सरकार से असंतुष्ट है और चुनाव में 'मौन क्रांति' देखने को मिल सकती है।

तिरुचिरापल्ली में पत्रकारों से बातचीत के दौरान दिनाकरन ने सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की आलोचना करते हुए कहा कि यह दल अपनी कमजोरी छिपाने के लिए लगातार अपने गठबंधन का विस्तार कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्री जे. जयललिता के कार्यकाल में उच्च पदों पर रहे कई नेता, जो अब राजनीतिक रूप से प्रभावहीन हो चुके हैं, आर्थिक रूप से मजबूत होने के बाद द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के गठबंधन में शामिल किए जा रहे हैं। दिनाकरन ने कहा कि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यह दावा करती है कि वह अपने सहयोगी दलों के कारण मजबूत है और इसी कारण उसने पिछला चुनाव जीता था। लेकिन उन्होंने सवाल उठाया कि यदि दल पहले से ही मजबूत है, तो उसे अपने गठबंधन में और दलों को शामिल करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। उनके अनुसार इसका कारण राज्य की वर्तमान सरकार के प्रति जनता में बढ़ती नाराजगी है।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2011 के चुनावों से पहले भी जनता की नाराजगी खुलकर दिखाई नहीं दी थी और परिणाम आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हुई थी। इसी तरह आगामी चुनावों में भी जनता 'मौन क्रांति' के माध्यम से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को सत्ता में ला सकती है।

सीट बंटवारे की बातचीत में देरी के प्रश्न पर दिनाकरन ने कहा कि गठबंधन में शामिल दलों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध हैं और सीटों को लेकर चर्चा जारी है। उन्होंने कहा कि सीट बंटवारा एक महत्वपूर्ण विषय है और इसमें समय लगना स्वाभाविक है।

दिनाकरन ने द्रविड़ मुनेत्र कड़गम सरकार पर चुनावी वादे पूरे न करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा को समाप्त करने का वादा किया था, लेकिन इसे पूरा नहीं किया गया। इसके साथ ही उन्होंने राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने और महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ने का भी आरोप लगाया।

एक्टर विजय का डीएमके पर तीखा वार

बोले- जनता इस Failed सरकार को सत्ता से बेदखल करने को तैयार है

चेन्नई। तमिलनाडु में हाल ही में हुई आपराधिक घटनाओं, जिनमें नवजात शिशुओं पर हमले से लेकर बुजुर्ग महिलाओं पर हमले तक शामिल हैं, ने टीवीके प्रमुख विजय को राज्य सरकार पर जन सुरक्षा बनाए रखने में विफल रहने का आरोप लगाने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने कहा कि लोग अब गैर-जिम्मेदार, विफल डीएमके सरकार को सत्ता से हटाने का इंतजार कर रहे हैं।

गुरुवार को एक्स पर एक पोस्ट में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को संबोधित करते हुए विजय ने सवाल उठाया कि क्या सत्तारूढ़ पार्टी की प्राथमिकता डीएमके गठबंधन को बनाए रखना है या राज्य में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा करना है।

विजय ने एक्स पर पोस्ट किया कि मुख्यमंत्री महोदय, जो पूरी तरह से अपने डीएमके गठबंधन को बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, तमिलनाडु में महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा कहां है? पोस्ट में आगे कहा गया कि तमिलनाडु की जनता इस गैर-जिम्मेदार, विफल डीएमके सरकार को सत्ता से हटाने का इंतजार कर रही है, जिसने कानून व्यवस्था बनाए रखने और महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के अपने कर्तव्य की उपेक्षा की है।

उन्होंने हाल के दिनों में सामने आई अपराध की कई घटनाओं पर प्रकाश डाला, जिनमें थूथुकुडी में 17 वर्षीय लड़की की हत्या और मदुरंथकम के पास 14 वर्षीय लड़की के साथ यौन उत्पीड़न शामिल है। उन्होंने यह भी कहा कि आम नागरिकों से लेकर राजनेताओं तक, कोई भी सुरक्षित नहीं है, और हाल ही में राजनीतिक नेताओं पर हुए हमलों का जिक्र किया, जैसे कि शिवगंगा के सांसद कार्ति चिदंबरम पर पेट्रोल बम फेंके गए।

केंद्रीय मंत्री व सांसद सिंधिया के प्रयासों से अशोकनगर और कोलारस को रेल कनेक्टिविटी की बड़ी सौगात

नई दिल्ली/अशोकनगर/शिवपुरी केन्द्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री तथा गुना सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रयासों से अशोकनगर और कोलारस क्षेत्र की जनता को बेहतर रेल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। रेल मंत्रालय ने 12 मार्च को अशोकनगर में सोगरिया-दानापुर एक्सप्रेस (19801/02) तथा कोलारस में उज्जैनी एक्सप्रेस (14309/10) के स्टॉपेज को स्वीकृति दी है। यह निर्णय क्षेत्र के यात्रियों के लिए आवागमन को अधिक सुगम और सुविधाजनक बनाएगा। यह जानकारी केन्द्रीय मंत्री सिंधिया ने सोशल मीडिया फेसबुक पर पोस्ट कर साझा की है।

पत्र पर त्वरित कार्रवाई

विदित रहे कि केन्द्रीय मंत्री सिंधिया ने 26 फरवरी 2026 को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर अशोकनगर और कोलारस में इन ट्रेनों के ठहराव की आवश्यकता को रेखांकित किया था। उनके इस पत्र पर त्वरित संज्ञान लेते हुए रेल मंत्रालय ने दोनों स्टॉपेज को स्वीकृति प्रदान की है, जिससे क्षेत्र के नागरिकों को सीधी और बेहतर रेल सुविधा मिल सकेगी। अशोकनगर में सोगरिया-दानापुर एक्सप्रेस और कोलारस में उज्जैनी एक्सप्रेस के ठहराव से क्षेत्र के यात्रियों को देश के विभिन्न हिस्सों से बेहतर कनेक्टिविटी प्राप्त होगी। इससे न केवल दैनिक यात्रियों, छात्रों और व्यापारियों को सुविधा मिलेगी, बल्कि क्षेत्रीय आवागमन और आर्थिक गतिविधियों को भी नई गति मिलेगी।

रेल मंत्री के प्रति सिंधिया ने व्यक्त किया आभार

इस बड़ी सौगात पर सिंधिया ने केन्द्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जनता की सुविधा मोदी सरकार के लिए सर्वोपरि है और सभी मंत्रालय एक साथ मिलकर Whole of Government अप्रोच के साथ कार्य कर रहे हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह निर्णय अशोकनगर और कोलारस की जनता के लिए बड़ी राहत और सुविधा लेकर आएगा तथा क्षेत्र की कनेक्टिविटी को और अधिक सुदृढ़ करेगा।

जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण के लिए राज्य की व्यापक कार्ययोजना तैयार-मंत्री पंकजा मुंडे

दिव्यांश

मुंबई।जलवायु परिवर्तन केवल पर्यावरण से जुड़ा सीमित विषय नहीं है, बल्कि यह दुनिया के भविष्य से जुड़ा अत्यंत गंभीर, व्यापक और संवेदनशील मुद्दा है। इसी पृष्ठभूमि में महाराष्ट्र सरकार ने जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए एक व्यापक कार्ययोजना तैयार की है, ऐसी जानकारी पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री पंकजा मुंडे ने दी।

विधान परिषद में नियम 92 के अंतर्गत सदस्य सुनील शिंदे ने इस विषय पर आधे घंटे की चर्चा की।

पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री पंकजा मुंडे ने बताया कि वर्ष 2021 में राज्य ने जलवायु कार्य योजना तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की थी। इसके लिए एक विशेष समिति गठित की गई है और इस प्रक्रिया में 350 से अधिक विशेषज्ञों तथा अधिकारियों की भागीदारी है। इस योजना को केंद्र सरकार की भी स्वीकृति मिल चुकी है।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2015 से 2025 के बीच, विशेष रूप से 2025 अब तक का सबसे अधिक गर्म वर्ष दर्ज किया गया है। पिछले 50 वर्षों में अत्यधिक गर्म

और बेहद गर्म दिनों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

मंत्री पंकजा मुंडे ने बताया कि जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से महाराष्ट्र देश के सबसे संवेदनशील पाँच राज्यों में शामिल है। राज्य तेजी से विकास कर रहा है और बड़े पैमाने पर सड़कें, उद्योग तथा अन्य बुनियादी ढांचे का निर्माण हो रहा है। ऐसे में विकास प्रक्रिया के साथ जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को ध्यान में रखते हुए यह कार्ययोजना तैयार की गई है। इस योजना में 'रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज़, रीसायकल और रिकवर' के पाँच सिद्धांतों पर विशेष जोर दिया गया है।

उन्होंने बताया कि कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए 'डिकार्बोनाइजेशन' पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत कुछ अमृत शहरों में प्रायोगिक परियोजनाएँ शुरू की गई हैं और उन शहरों के लिए अलग-अलग जलवायु कार्य योजनाएँ तैयार की गई हैं।

अगले चरण में प्रत्येक जिले के लिए वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर अलग योजना तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसमें जिले की फसल पद्धति, नदियों की स्थिति, वर्षा की मात्रा, मिट्टी के प्रकार तथा प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों का अध्ययन कर आवश्यक उपाय तय किए जाएंगे।

मंत्री पंकजा मुंडे ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को पूरी तरह रोकना संभव नहीं है, लेकिन राज्य सरकार विकास प्रक्रिया के साथ उसके दुष्प्रभावों को कम करने और संतुलित करने के लिए ठोस कदम उठा रही है।

संजय राउत का पीएम मोदी पर तीखा हमला, बोले- देश में एलपीजी संकट, प्रधानमंत्री रैली में व्यस्त

मुंबई। शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने गुरुवार को केरल और तमिलनाडु में रैलियां करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की और उनसे व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों की कथित कमी पर ध्यान देने की मांग की। राष्ट्रीय राजधानी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, संजय राउत ने केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना की और पश्चिम एशिया संघर्ष के भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा की मांग की।

राउत ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री कहां हैं? वे केरल और तमिलनाडु में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और वे अपने विरोधियों के खिलाफ जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वे प्रधानमंत्री पद की गरिमा के अनुरूप नहीं हैं। आप ईरान-इजराइल संघर्ष के प्रभाव पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। आप (केंद्र) एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की कमी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। यह स्थिति लोगों में भय पैदा कर रही है। होटल और रेस्तरां बंद हो रहे हैं। मोदी सरकार ने इस पर कुछ नहीं कहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश ऐसे नेतृत्व के हाथों में है।

यह घटनाक्रम गुरुवार को केरल और तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले प्रधानमंत्री मोदी की जनसभाओं के बाद सामने आया है। प्रधानमंत्री ने डीएमके, कांग्रेस और वाम गठबंधन पर निशाना साधते हुए पश्चिम एशिया संघर्ष पर भी बात की। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया की स्थिति ने विश्व की ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित किया है और उनकी सरकार 'इंडिया फर्स्ट' की विचारधारा में विश्वास रखती है।

तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार भारतीयों के हितों को सर्वोपरि रखने के उसी दृष्टिकोण का पालन करेगी और घबराने या अफवाहों पर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज मैं तमिलनाडु के लोगों से पश्चिम एशिया संघर्ष के बारे में बात करना चाहता हूं। इसने पूरी दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित किया है। हम 'इंडिया फर्स्ट' की विचारधारा में विश्वास रखते हैं। खबरों के मुताबिक, पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के मद्देनजर व्यावसायिक एलपीजी गैस सिलेंडरों की कमी हो गई है, जिसके बाद केंद्र ने घरेलू खपत को प्राथमिकता देते हुए आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू किया है।

पश्चिम रेलवे का गैर-किराया राजस्व दोगुना करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य

प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा भारतीय रेल के गैर-किराया राजस्व बढ़ाने के निर्देशों के अनुरूप पश्चिम रेलवे ने गैर-किराया स्रोतों से अपनी आय में उल्लेखनीय वृद्धि करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, पश्चिम रेलवे के प्रमुख मुख्य वाणिज्य प्रबंधक श्री तरुण जैन ने गैर-किराया राजस्व बढ़ाने की रणनीतियों पर चर्चा के लिए वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधकों के साथ एक उच्चस्तरीय विचार-मंथन बैठक की अध्यक्षता की।

बैठक के दौरान श्री तरुण जैन ने कहा कि यात्रियों को मूल्यवर्धित सेवाएँ उपलब्ध कराना हमारा प्रमुख उद्देश्य है। उन्होंने बताया कि डिजिटल लाउंज और मिनी मॉल जैसी पहलों की सफलता से यह स्पष्ट हुआ है कि यात्री अब आधुनिक, प्रौद्योगिकी आधारित और गुणवत्तापूर्ण सेवाओं की ओर अधिक आकर्षित हो रहे हैं। गैर-किराया राजस्व को दोगुना कर पश्चिम रेलवे अपनी वाणिज्यिक परिसंपत्तियों की आय क्षमता को नए दृष्टिकोण से विकसित करना चाहता है।

चालू वित्तीय वर्ष में फरवरी 2026 तक पश्चिम रेलवे ने गैर-किराया राजस्व के रूप में 117 करोड़ रुपये अर्जित किए हैं, जिससे यह बेहतर प्रदर्शन करने वाले जोनों में शामिल हो गया है। भारतीय रेल के गैर-किराया राजस्व को 750 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1500 करोड़ रुपये करने के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप पश्चिम रेलवे ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 239.24 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया है।

श्री तरुण जैन ने बताया कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुंबई सेंट्रल स्थित डिजिटल लाउंज, रतलाम स्टेशन पर मिनी मॉल तथा अहमदाबाद में वातानुकूलित सह डिजिटल लाउंज जैसी सफल पहलों को अन्य स्थानों पर भी लागू करने की आवश्यकता है। इन पहलों का उद्देश्य यात्रियों की सुविधा और आराम को अधिकतम करना है।

उन्होंने आगे कहा कि अब समय आ गया है कि पारंपरिक विज्ञापन के दायरे से आगे बढ़कर नवोन्मेषी दृष्टिकोण अपनाए जाएँ। बैठक में जिन नई पहलों पर चर्चा हुई, उनमें उपयुक्त स्थानों पर ब्रांडेड कियोस्क और अनुभव केंद्र स्थापित करना, परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण, अधिक यात्री आवागमन वाले स्टेशनों पर डिजिटल बाहरी विज्ञापन का विस्तार तथा रेलवे स्टेशनों को जीवंत वाणिज्यिक केंद्रों के रूप में विकसित करना शामिल है।

रतलाम मंडल ने वित्तीय वर्ष 2025-26 का टिकट चेकिंग लक्ष्य सफलतापूर्वक किया पूर्ण

24 करोड़ से अधिक राजस्व अर्जित कर आंतरिक लक्ष्य भी किया पार

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

रतलाम। पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल ने टिकट चेकिंग के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए निर्धारित टिकट चेकिंग लक्ष्य को समय से पूर्व सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है। मंडल द्वारा निर्धारित 22.59 करोड़ के लक्ष्य के सापेक्ष 24 करोड़ से अधिक का राजस्व अर्जित किया गया है। यह आंकड़ा रतलाम मंडल ने 10 मार्च, 2026 को प्राप्त कर लिया है।

पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के जनसंपर्क अधिकारी श्री मुकेश कुमार द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, रतलाम मंडल का आंतरिक टिकट चेकिंग लक्ष्य 24 करोड़ निर्धारित किया गया था, जिसे

दिनांक 10 मार्च 2026 को सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया गया। यह उपलब्धि वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक के कुशल मार्गदर्शन के साथ ही मंडल वाणिज्य प्रबंधक एवं सहायक वाणिज्य प्रबंधक के निर्देशन में मंडल के कर्मयोगी टिकट चेकिंग स्टाफ एवं वाणिज्य विभाग के सतत प्रयासों, प्रतिबद्धता एवं कर्तव्यनिष्ठा का परिणाम है।

रतलाम मंडल द्वारा निरंतर सघन टिकट जांच अभियानों, बिना टिकट यात्रा पर प्रभावी नियंत्रण तथा यात्रियों में जागरूकता बढ़ाने के माध्यम से राजस्व वृद्धि सुनिश्चित की गई। इस उल्लेखनीय उपलब्धि से न केवल रेलवे राजस्व में वृद्धि हुई है, बल्कि टिकट रहित यात्रा पर भी प्रभावी अंकुश लगा है।

प्रधान कार्यालय द्वारा दिये लक्ष्य को समय पूर्व पूरा करना न केवल मंडल के चेकिंग स्टाफ के कार्यकुशलता का प्रतिबिंब है बल्कि ये उपलब्धियां कर्मयोगी कर्मचारियों को और उत्साह से कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है।

इंदौर-दाहोद नई रेल लाइन परियोजना में तेजी

रोड ओवर ब्रिज संख्या 202 ए की एक लेन से आवागमन प्रारंभ

रतलाम। पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल की महत्वाकांक्षी इंदौर-दाहोद नई रेल लाइन परियोजना पर तेजी से कार्य जारी है। परियोजना के अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर रेल ओवर ब्रिज एवं अन्य संरचनात्मक कार्यों को शीघ्रता से पूर्ण किया जा रहा है, ताकि रेलवे ट्रैक लिंकिंग तथा अन्य निर्माण कार्यों को निर्धारित समयसीमा में आगे बढ़ाया जा सके। इसी क्रम में इंदौर से धार के मध्य स्थित रोड ओवर ब्रिज संख्या 202 ए की एक लेन का निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद इसे सड़क यातायात के लिए खोल दिया गया है।

इससे पूर्व 28 फरवरी को सागौर-गुणावद के मध्य स्थित रोड ओवर ब्रिज संख्या 234 ए एवं 221 ए को भी सड़क यातायात के लिए खोल दिया गया था। इन दोनों ब्रिजों के शुरू होने से क्षेत्र में रेलवे ट्रैक लिंकिंग का कार्य काफी सुगम हो गया है और निर्माण कार्यों को गति मिली है। इसी कड़ी में रोड ओवर ब्रिज संख्या 202 ए की एक लेन का कार्य पूर्ण होने के बाद 12 मार्च से इस पर वाहनों का आवागमन प्रारंभ कर दिया गया है।

पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के जनसंपर्क अधिकारी श्री मुकेश कुमार द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार यह रोड ओवर ब्रिज चार लेन का है। वर्तमान में यातायात की सुविधा के लिए दो लेन को प्राथमिकता के आधार पर चालू किया जा रहा है, जबकि शेष दो लेन का निर्माण कार्य भी तेजी से प्रगति पर है और इसके अप्रैल 2026 के अंत तक पूर्ण होने की संभावना है। चारों लेन तैयार होने के बाद इस रोड ओवर ब्रिज का औपचारिक लोकार्पण किया जाएगा।

ब्रिज को यातायात के लिए खोलने से पूर्व इसका तकनीकी मानकों के अनुरूप लोड टेस्ट किया गया, जिसके सफलतापूर्वक पूर्ण होने के बाद ही इसे आम जनता के लिए खोला गया है। इससे सड़क उपयोगकर्ताओं को सुरक्षित एवं सुगम आवागमन की सुविधा मिलेगी।

रोड ओवर ब्रिज के शुरू होने से निर्माणाधीन रेलवे लाइन के ऊपर से वाहनों का आवागमन सुनिश्चित होगा, जिससे नीचे रेल पथ पर ट्रैक लिंकिंग, मरम्मत तथा अन्य तकनीकी कार्यों को बिना बाधा के किया जा सकेगा। इससे परियोजना के कार्यों को गति मिलने के साथ ही उन्हें गुणवत्तापूर्ण ढंग से निर्धारित समयसीमा में पूरा करने में भी मदद मिलेगी।

इंदौर-दाहोद नई रेल लाइन परियोजना पूर्ण होने के बाद मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच रेल संपर्क को नई मजबूती मिलेगी, साथ ही क्षेत्र के यात्रियों और व्यापारिक गतिविधियों को भी बड़ा लाभ होगा।

मुंबई से आईआरसीटीसी का विशेष यूरोप टूर पैकेज शुरू, 12 रात 13 दिन की अंतरराष्ट्रीय यात्रा

मुंबई। भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) के पश्चिम क्षेत्र, मुंबई द्वारा यात्रियों के लिए विशेष एमओएसडी यूरोप टूर पैकेज की शुरुआत की गई है। यह 12 रात और 13 दिन का अंतरराष्ट्रीय भ्रमण 26 अप्रैल 2026 को मुंबई से रवाना होगा और 8 मई 2026 को वापस लौटेगा।

इस विशेष यात्रा में देशभर से लगभग 70 से 80 यात्रियों के शामिल होने की संभावना है। इस टूर के संचालन और समन्वय की जिम्मेदारी आईआरसीटीसी पश्चिम क्षेत्र, मुंबई द्वारा निभाई जाएगी।

इस टूर पैकेज के अंतर्गत यात्रियों को यूरोप के प्रमुख शहरों–पेरिस, ब्रुसेल्स, एम्स्टर्डम, कोलोन, मैनहेम, ज्यूरिख, इंसब्रुक, वेनिस, पीसा, फ्लोरेंस, रोम और मिलान–का भ्रमण कराया जाएगा। इस यात्रा का मुख्य आकर्षण नीदरलैंड्स स्थित विश्व प्रसिद्ध क्यूकेनहॉफ ट्यूलिप गार्डन का दौरा होगा, जो वसंत ऋतु में खिले रंग-बिरंगे ट्यूलिप फूलों के लिए विश्वभर में प्रसिद्ध है।

यात्रियों की सुविधा और आराम को ध्यान में रखते हुए इस पैकेज में आने-जाने की इकोनॉमी श्रेणी की हवाई यात्रा, तीन से चार सितारा होटलों में ठहरने की व्यवस्था, भारतीय तथा कॉन्टिनेंटल भोजन, स्थानीय परिवहन सुविधा,

मार्गदर्शक के साथ दर्शनीय स्थलों का भ्रमण, प्रमुख आकर्षणों के प्रवेश शुल्क, वीज़ा सहायता, यात्रा बीमा और लागू जीएसटी शामिल किए गए हैं।

आईआरसीटीसी पश्चिम क्षेत्र के समूह महाप्रबंधक श्री गौरव झा ने बताया कि आईआरसीटीसी के अंतरराष्ट्रीय टूर पैकेज प्रतिस्पर्धी कीमतों पर उत्कृष्ट सेवाएं और भरोसेमंद आतिथ्य प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि इस एमओएसडी यूरोप टूर पैकेज को यात्रियों से काफी उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिल रही है।

इस टूर के लिए बुकिंग आईआरसीटीसी की आधिकारिक वेबसाइट, देशभर में अधिकृत आईआरसीटीसी एजेंटों या व्हाट्सएप/संदेश नंबर 8287931886 के माध्यम से की जा सकती है।

आईआरसीटीसी देश और विदेश में विभिन्न पर्यटन पैकेजों के माध्यम से यात्रियों को सुरक्षित, सुविधाजनक और यादगार यात्रा अनुभव उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

मध्य रेल आने वाली ग्रीष्मकालीन छुट्टियों को ध्यान में रखते हुए 1484 ग्रीष्मकालीन विशेष ट्रेनों की घोषणा की

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मध्य रेल ने यात्रियों को अपने प्रियजनों के साथ गर्मी की छुट्टियां बिताने में सुविधा प्रदान करने के लिए विभिन्न गंतव्यों के लिए 1484 ग्रीष्मकालीन ट्रेनों की घोषणा की है। इनमें 749 आरक्षित और 735 अनारक्षित विशेष ट्रेनें शामिल हैं।

इन ग्रीष्मकालीन ट्रेनों में पहले से ही ऑन-डिमांड चलने वाली ट्रेन सेवाएं और कुछ अतिरिक्त विशेष ट्रेनें शामिल हैं।

महाराष्ट्र के भीतर गंतव्यों के लिए विशेष ट्रेन सेवाओं में मुंबई/दौंड-सोलापुर, पुणे-कोल्हापुर, नाशिक रोड-बडनेरा और हडपसर-हरंगुल के बीच चलने वाली ट्रेनें शामिल हैं।

महाराष्ट्र के बाहर गंतव्यों के लिए विशेष ट्रेन सेवाओं में मुंबई-बलिया, मुंबई-गोरखपुर, दौंड-कलबुरगि और सोलापुर-कलबुरगि/अनकापल्ले के बीच चलने वाली ट्रेनें शामिल हैं।

ये विशेष ट्रेनें यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना बनाने में सहायक होंगी। यात्रियों की सुविधा और आराम सुनिश्चित करने के लिए, मध्य रेल ने अपने पूरे नेटवर्क में यात्री सुविधाओं को बढ़ाया है और कई उपाय लागू किए हैं। इन विशेष ट्रेनों के विस्तृत समय और ठहराव की जानकारी शीघ्र ही दी जाएगी।

राज्य में क्षेत्रीय पर्यटन योजना के तहत 50 पर्यटन स्थलों का विकास किया जाएगा- वित्त एवं नियोजन राज्य मंत्री आशीष जायसवाल

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मुंबई। राज्य में पर्यटन विकास के लिए प्रचुर प्राकृतिक संसाधन, ऐतिहासिक धरोहर और धार्मिक स्थल उपलब्ध हैं। इन संसाधनों का पर्यटन की दृष्टि से उचित उपयोग कर विकसित महाराष्ट्र 2047 के संकल्प को ध्यान में रखते हुए राज्य की अर्थव्यवस्था को बड़ा प्रोत्साहन दिया जाएगा। क्षेत्रीय पर्यटन योजना के माध्यम से राज्य के 50 पर्यटन स्थलों का विकास किया जाएगा। साथ ही इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले में कम से कम एक पर्यटन स्थल विकसित किया जाएगा, ऐसी जानकारी वित्त एवं नियोजन राज्य मंत्री आशीष जायसवाल ने विधान परिषद में दी।

विधान परिषद में नियम 92 के अंतर्गत सदस्य रणजीतसिंह मोहिते पाटिल ने उजनी बांध क्षेत्र के पर्यटन विकास को लेकर आधे घंटे की चर्चा प्रस्तुत की थी।

राज्य मंत्री आशीष जायसवाल ने कहा कि महाराष्ट्र को प्रचुर जल संसाधन, विस्तृत समुद्र तट, ऐतिहासिक किले और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का वरदान प्राप्त है। इसके अलावा राज्य में कई विश्व धरोहर स्थल और धार्मिक पर्यटन स्थल भी मौजूद हैं। जल क्रीड़ा, वन पर्यटन, ऐतिहासिक धरोहर स्थल और धार्मिक पर्यटन पर्यटन विकास के

चार महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। राज्य सरकार ने इन पर्यटन स्थलों के माध्यम से राज्य में पर्यटकों की संख्या बढ़ाने और पर्यटन के जरिए बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन को प्राथमिकता दी है।

उन्होंने बताया कि उजनी बांध क्षेत्र के पर्यटन विकास के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है और इस क्षेत्र को प्रभावी रूप से विकसित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

राज्य मंत्री जायसवाल ने कहा कि उजनी बांध परियोजना में पर्यटन से जुड़े कार्यों के लिए जल संसाधन विभाग की अनुमति आवश्यक है। यदि जल संसाधन विभाग, पर्यटन विभाग और अन्य संबंधित विभाग समन्वय के साथ निर्णय लें, तो राज्य के जल संसाधनों का पर्यटन के लिए प्रभावी उपयोग किया जा सकता है।

उन्होंने आगे कहा कि जन-निजी भागीदारी के माध्यम से पर्यटन परियोजनाओं को गति दी जाएगी। साथ ही उजनी बांध परियोजना का दौरा कर वहाँ चल रही पर्यटन परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा।

पश्चिम रेलवे – रतलाम मंडल

ई-निविदा सूचना

निविदा संख्या: SnT_RTM_26_02_SIGNAL, दिनांक: 10.03.2026. कार्य का नाम: बेराच केबिन में एक साथ रिसेप्शन सुविधा के साथ पूर्ण लंबाई की दूसरी लूप लाइन के प्रावधान के संबंध में सिग्नलिंग सामग्री की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग। **कार्य की अनुमानित लागत:** रु 1,13,44,412.04. **बयाना राशि:** रु 2,06,700/-. **निविदा बंद करने का समय एवं दिनांक:** दिनांक 07.04.2026 समय 15:00 बजे तक। **निविदा खुलने का समय एवं दिनांक:** दिनांक 07.04.2026 समय 15:30 बजे के बाद। **कार्य पूरा करने की अवधि:** 09 माह। **निविदा अनुभाग कार्यालय प्रभारी और बोली खोलने का स्थान:** सीनियर डीएसटीई रतलाम, डीआरएम कार्यालय रतलाम म.प्र. निविदा सिर्फ ऑनलाइन E-निविदा पोर्टल www.ireps.gov.in पर देखा व जमा किया जा सकता है। DE/6/1/506

हमें लाईक करें: facebook.com/WesternRly

मध्य रेल

सोलापुर मण्डल

पुनर्निमाण कार्य

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर (क.वि), मध्य रेल, सोलापुर, निम्नलिखित कार्य के लिए ख्याति प्राप्त, अनुभवी और लाईसेंसधारी विद्युत ठेकेदारों से रेल्वे की ई प्रोक्यूरमेंट वेबसाइट **www.ireps.gov.in** पर ऑनलाइन ई निविदा आमंत्रित करते हैं। **निविदा क्रं :** सोला/क.वि./नि/2026/04। **कार्य का नाम :** निम्नलिखित के संबंध मे विद्युत टीआरडी का कार्य, 1) मोहोल-वाडी खंड में 11 पुलों (स्लैब: 06, आरसीसी पाइप: 03, आर्च ब्रिज: 02) का पुनर्निमाण और 6 पुलों (आर्च: 05, बॉक्स: 01) का विस्तार, 2) कुलाली-वाडी खंड में पुल संख्या 552/1, 552/2, 557/3, 557/4 और 557/5 (कुल 1000*2=2000 मीटर) के पहुंच मार्गों के लिए टो वॉल म्यूरोम फिलिंग, बोल्डर पिचिंग और 2:1 ढलान द्वारा बैंक की सव-बैंक ड्रेसिंग तैयार करके कमजोर साइड स्लोप को मजबूत करना। 3) कुर्दुवाडी - लातूर खंड में सुरंग संख्या 2 के अंदर महत्वपूर्ण स्थानों पर पोर्टल, शॉटक्रेटिंग, रॉक वोल्टिंग आदि जैसे स्टेबलिंग और सपोर्टिंग कार्यों का प्रावधान। **कार्य की अनुमानित लागत :** ₹ 45,19,663/-। **बयाना राशि :** ₹ 90,400/-। **कार्य पुरा करने की अवधि :** 12 माह। **निविदा प्रस्ताव की वैधता :** 60 दिन। **वेबसाइट पर निविदा बंद होने की तिथि और समय :** दि. 08.04.2026 को 15.00 बजे। EXP-13

टिकट के लिए RailOne App डाउनलोड करे

गैस सिलेंडर की सुचारु आपूर्ति के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग सक्रिय

राज्यभर में नियंत्रण कक्ष स्थापित, जिलास्तरीय समितियों का गठन

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मुंबई।ईरान-इज़राइल युद्ध की पृष्ठभूमि में घरेलू और व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की आपूर्ति सुचारु बनाए रखने के लिए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न उपाय लागू किए जा रहे हैं। घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडरों की आपूर्ति में किसी प्रकार की बाधा न आए और संभावित कमी की स्थिति में समन्वय स्थापित किया जा सके, इसके लिए राज्य सरकार ने जिलास्तर पर विशेष समितियाँ गठित करने का निर्णय लिया है।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनिल दिग्गीकर ने राज्यभर में एलपीजी की आपूर्ति बनाए रखने और उसके नियंत्रण के लिए संबंधित एजेंसियों को आवश्यक उपाय करने के निर्देश दिए हैं।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने नागरिकों को आश्वस्त किया है कि घरेलू गैस सिलेंडरों की आपूर्ति सुचारु रूप से जारी रहेगी।

मार्च महीने में पिछले छह महीनों की तुलना में अधिक घरेलू गैस सिलेंडर उपलब्ध हैं। युद्ध की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए घरेलू गैस सिलेंडरों की आपूर्ति में किसी प्रकार की बाधा न आए, इसके लिए विभाग ने सभी संबंधित एजेंसियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं।

जिलास्तर पर विशेष समितियों का गठन

घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडरों की आपूर्ति में किसी प्रकार का व्यवधान न आए और संभावित कमी की स्थिति में समन्वय स्थापित करने के लिए राज्य सरकार ने जिलास्तर पर विशेष समितियाँ गठित करने का निर्णय लिया है। इन समितियों में जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, जिला आपूर्ति अधिकारी तथा सभी सरकारी गैस कंपनियों के अधिकारी शामिल होंगे। इन समितियों की मुख्य जिम्मेदारी गैस आपूर्ति श्रृंखला की निगरानी करना, कानून-व्यवस्था बनाए रखना तथा स्थिति की दैनिक समीक्षा कर रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा।

मुंबई-ठाणे राशनिंग क्षेत्र में नियंत्रक राशनिंग के नियंत्रण में गठित समिति में पुलिस उपायुक्त और उप नियंत्रक (राशनिंग) शामिल होंगे तथा मुंबई और ठाणे शहरों में सभी पुलिस उपायुक्तों के साथ समन्वय संयुक्त पुलिस आयुक्त (प्रशासन) करेंगे।

एजेंसियों को वैकल्पिक ईंधनों के उपयोग की संभावनाओं की भी जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। कोयला और मिट्टी के तेल जैसे विकल्पों पर विचार किया जाएगा, लेकिन इसके लिए महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल के नियमों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।

जिलास्तरीय समितियों ने होटल और रेस्टोरेंट संघों के साथ बैठक कर वैकल्पिक ईंधनों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के निर्देश भी दिए हैं।

आवश्यक सेवाओं को प्राथमिकता

अस्पतालों, सरकारी छात्रावासों, सरकारी विद्यालयों और महाविद्यालयों के भोजनालयों, मध्याह्न भोजन योजना, सरकारी आश्रम विद्यालयों आदि आवश्यक सेवाएँ प्रदान करने वाली संस्थाओं को घरेलू तथा व्यावसायिक गैस आपूर्ति में प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसी संस्थाओं की सूची तैयार कर उन्हें प्राथमिकता के आधार पर एलपीजी उपलब्ध कराई जाएगी।

गैस आपूर्ति को लेकर अफवाहों को रोकने के लिए रेडियो, एफएम, दूरदर्शन और समाचार पत्रों के माध्यम से प्रतिदिन जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग तथा जिलास्तरीय समितियाँ इस कार्य के लिए जिम्मेदार होंगी और सामाजिक माध्यमों पर फैल रही झूठी खबरों के खिलाफ कार्रवाई भी करेंगी।

तेल कंपनियों को गैस बुकिंग अनुप्रयोग और मिस्ड कॉल सेवाओं में आने वाली तकनीकी समस्याओं को तुरंत दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य, संभाग, जिला और तालुका स्तर पर नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किए जाएंगे तथा शिकायत निवारण के लिए व्हाट्सऐप सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।

आगामी धार्मिक उत्सवों को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक संस्थानों को एलपीजी सिलेंडरों की निर्बाध आपूर्ति बनाए रखने को प्राथमिकता दी जाएगी।

नागरिकों में घबराहट की स्थिति न बने, इसके लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्राम पंचायत सदस्यों की सहायता लेने के निर्देश भी दिए गए हैं। एलपीजी सिलेंडर ले जाने वाले वाहनों तथा गैस एजेंसियों को आवश्यक पुलिस सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन को सौंपी गई है।

जिला प्रशासन, राशनिंग नियंत्रक और तेल कंपनियों को प्रतिदिन गैस भंडार की स्थिति और अद्यतन रिपोर्ट राज्यस्तरीय नियंत्रण कक्ष को भेजना अनिवार्य किया गया है।

राज्य में घरेलू एलपीजी की कोई कमी नहीं

महाराष्ट्र में प्रतिदिन एलपीजी की औसत मांग लगभग 9,000 मीट्रिक टन है। इस मांग को पूरा करने के लिए रिफाइनरियों में एलपीजी उत्पादन बढ़ाया गया है। पिछले दो दिनों में दैनिक उत्पादन 9,000 मीट्रिक टन से बढ़कर लगभग 11,000 मीट्रिक टन हो गया है। इसलिए यह स्पष्ट किया गया है कि राज्य में घरेलू एलपीजी की कोई कमी नहीं है और मांग पूरी करने के लिए पर्याप्त उत्पादन तथा भंडार उपलब्ध है।

व्यावसायिक एलपीजी के मामले में केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्राथमिकताएँ तय की गई हैं। इसके तहत अस्पतालों, स्कूलों की मध्याह्न भोजन योजना, सरकारी आश्रम विद्यालयों, सामुदायिक रसोई और सरकारी विद्यालय-महाविद्यालयों के भोजनालयों को प्राथमिकता दी जा रही है।

घरेलू उपयोग के लिए पाइप से मिलने वाली प्राकृतिक गैस का भी पर्याप्त भंडार उपलब्ध है।

महाराष्ट्र विधानसभा में बम की धमकी निकली झूठी; जांच में नहीं मिला कुछ भी संदिग्ध

मुंबई। मुंबई के महाराष्ट्र विधान भवन में गुरुवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब एक धमकी भरा ईमेल मिला। इस ईमेल में विधान भवन को बम से उड़ाने की बात कही गई थी। जिस समय

यह धमकी मिली, वहां बजट सत्र की कार्यवाही चल रही थी। इस संदेश के मिलते ही सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस प्रशासन तुरंत अलर्ट हो गए।

एहतियात के तौर पर दक्षिण मुंबई में स्थित इस परिसर से कर्मचारियों और अन्य लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। पुलिस ने तुरंत सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। बम निरोधक दस्ता और खोजी कुत्तों की टीम मौके पर पहुंच गई। सुरक्षाकर्मियों ने पूरी इमारत के चप्पे-चप्पे की तलाशी ली। काफी देर तक चली जांच के बाद वहां कोई भी बम या संदिग्ध वस्तु नहीं मिली।

जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने साफ कर दिया कि यह धमकी पूरी तरह झूठी थी। किसी ने शरारत के मकसद से यह फर्जी ईमेल भेजा था। अब पुलिस उस व्यक्ति की पहचान करने में जुटी है जिसने यह ईमेल भेजा था। पुलिस साइबर सेल की मदद से ईमेल के आईपी एड्रेस और भेजने वाले के ठिकाने का पता लगा रही है। फिलहाल विधान भवन में स्थिति सामान्य है और सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है।

पुणे, पिंपरी-चिंचवड़ और हिंजेवाड़ी आईटी क्षेत्र में यातायात प्रबंधन होगा अधिक प्रभावी- शहरी विकास राज्य मंत्री माधुरी मिसाल

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मुंबई : शहरी विकास राज्य मंत्री माधुरी मिसाल ने बताया कि पुणे, पिंपरी-चिंचवड़ और हिंजेवाड़ी राज्य के महत्वपूर्ण आईटी और औद्योगिक क्षेत्र हैं, जहाँ एमआईडीसी सहित बड़ी संख्या में उद्योग और आईटी कंपनियाँ कार्यरत हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निर्देशानुसार इस क्षेत्र के विकास के लिए एक रणनीतिक योजना तैयार की जा रही है।

उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत 18 मीटर और 24 मीटर चौड़ाई की नई सड़कों का प्रस्ताव किया गया है। इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, रिंग रोड, विकास योजना सड़कें, आंतरिक सड़कें और प्रमुख प्रवेश मार्गों को शामिल किया गया है। इसके साथ ही स्वामीनारायण मंदिर से भूमकर पुल और नवले पुल क्षेत्र तक कार्य जारी है तथा पिंपरी-चिंचवड़ महानगरपालिका की ओर जाने वाली अतिरिक्त सेवा सड़कों के लिए निविदा प्रक्रिया और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया भी चल रही है।

मंत्री माधुरी मिसाल ने बताया कि नरे से लवण पुल के लिए लगभग 3,660 करोड़ रुपये का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है और नाशिक फाटा से केल मार्ग पर आठ लेन के पुल को भी मंजूरी मिल चुकी है। रिंग रोड परियोजना के लिए आवश्यक भूमि अधिग्रहण हेतु राज्य सरकार लगभग 600 करोड़ रुपये की निधि उपलब्ध कराएगी।

उन्होंने कहा कि मेट्रो परियोजनाओं के संबंध में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। पीसीएमपी से फुगेवाड़ी, फुगेवाड़ी से जिला न्यायालय, जिला न्यायालय से स्वारगेट तथा वनाज से गरवारे कॉलेज मार्गों पर कार्य चल रहा है। साथ ही हिंजेवाड़ी से शिवाजीनगर मेट्रो परियोजना का लगभग 98 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है।

मंत्री मिसाल ने बताया कि नाशिक फाटा से आरटीओ होते हुए पुराने मुंबई-पुणे मार्ग तक भोसरी गाँव क्षेत्र में सड़कों के लिए 100 प्रतिशत भूमि अधिग्रहण पूरा हो चुका है और कुछ स्थानों पर कार्य शुरू भी हो गया है। भोसरी क्षेत्र में सर्पिल मार्ग के लिए भी लगभग 69 से 70 प्रतिशत भूमि अधिग्रहण पूरा हो चुका है।

यातायात प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित यातायात संकेत प्रणाली तथा आधुनिक यातायात नियोजन योजना तैयार की गई है। मंत्री माधुरी मिसाल ने स्पष्ट किया कि इन सभी परियोजनाओं के माध्यम से चरणबद्ध तरीके से यातायात जाम की समस्या का समाधान किया जाएगा।

इस विषय पर हुई चर्चा में विधानसभा सदस्य विजय वडेट्टीवार, राजेश पवार, शंकर जगताप, हेमंत रसाने और अधिवक्ता राहुल कुल ने भाग लिया।

नवी मुंबई में एचपीवी टीकाकरण अभियान का शुभारंभ, महापौर सुजाता पाटिल रहीं उपस्थित

सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए एचपीवी टीका एनएमएमसी के सभी अस्पतालों और नागरिक स्वास्थ्य केंद्रों में निःशुल्क उपलब्ध

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार एचपीवी टीकाकरण अभियान का राष्ट्रीय स्तर पर 28 फरवरी 2026 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुभारंभ किया गया था, जबकि राज्य स्तर पर इसका शुभारंभ अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किया गया। नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्र में इस टीकाकरण अभियान की शुरुआत आज सीबीडी बेलापुर स्थित शहरी स्वास्थ्य केंद्र में महापौर श्रीमती सुजाता पाटिल की उपस्थिति में की गई। इस अवसर पर स्वास्थ्य समिति के सभापति डॉ. जयाजी नाथ, नगरसेविका श्रीमती स्वाती गुरखे, वैद्यकीय स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. प्रशांत जवड़े तथा वैद्यकीय अधिकारी डॉ. अर्चना तायडे उपस्थित थीं।

इस अवसर पर महापौर की मौजूदगी में विद्याप्रसारक हाई स्कूल, बेलापुर की कक्षा 9 की छात्राएँ अनुष्का सोमनाथ कोली और अक्षता सचिन कातकरी तथा एनएमयूएमपीए स्कूल क्रमांक 4, सीबीडी बेलापुर की कक्षा 8 की छात्रा अनुजा शंभू मालेकर को एचपीवी टीका लगाया गया। साथ ही उन्हें प्रोत्साहन स्वरूप कम्पास बॉक्स भी भेंट किया गया।

कार्यक्रम में बोलते हुए महापौर सुजाता

पाटिल ने कहा कि कैंसर के बढ़ते मामलों और महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर की अधिक संख्या को देखते हुए इस टीके को एक महत्वपूर्ण रोकथाम उपाय के रूप में लेना आवश्यक है। प्रधानमंत्री की संकल्पना के अनुसार देशभर की बालिकाओं को इस बीमारी से सुरक्षित रखने के उद्देश्य से यह टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि वे जागरूक होकर अपनी बेटियों को यह टीका अवश्य लगवाएं।

उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि इस अभियान की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए सभी स्कूलों, महानगरपालिका के अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों के साथ-साथ व्यस्त सार्वजनिक स्थानों पर बैनर लगाए जाएँ।

इस अभियान के अंतर्गत 14 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी और 15 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं को एचपीवी टीका लगाया जाएगा। अभियान शुरू होने के बाद अगले 90 दिनों के भीतर 15 वर्ष की आयु पूरी करने वाली बालिकाएँ भी इस तीन महीने के एचपीवी (ह्यूमन पैपिलोमा वायरस) टीकाकरण अभियान के लिए पात्र होंगी।

महानगरपालिका आयुक्त डॉ. कैलाश शिंदे के मार्गदर्शन में नवी मुंबई महानगरपालिका के 5 अस्पतालों और 26 नागरिक स्वास्थ्य केंद्रों में एचपीवी टीकाकरण की व्यवस्था की गई है। नगरपालिका क्षेत्र में 14 से 15 वर्ष की आयु वर्ग की सभी बालिकाओं को लक्षित करते हुए इस अभियान की योजना बनाई गई है। महानगरपालिका के सभी अस्पतालों और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ-साथ आईएमए, आईएपी, नीमा, हिम्पाम, निजी मेडिकल कॉलेजों और स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया गया है। इनके माध्यम से एचपीवी टीकाकरण के प्रति जनजागरूकता भी बढ़ाई जा रही है।

नगर आयुक्त डॉ. कैलाश शिंदे ने नवी मुंबई के अभिभावकों से अपील की है कि वे इस अभियान में सक्रिय रूप से भाग लें और 14 से 15 वर्ष की प्रत्येक बालिका को एचपीवी टीका लगवाकर सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षित बनाने में सहयोग करें।

यशवंतराव चव्हाण की जयंती पर प्रतिमा पूजन कर दी गई श्रद्धांजलि

महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री तथा देश के पूर्व उपप्रधानमंत्री स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण की जयंती के अवसर पर नवी मुंबई महानगरपालिका मुख्यालय में उनकी प्रतिमा का पूजन कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। यह पूजन महापौर श्रीमती सुजाता पाटिल के शुभ हाथों से संपन्न हुआ।

इस अवसर पर स्वास्थ्य समिति के सभापति डॉ. जयाजी नाथ, प्रशासन विभाग के उप आयुक्त श्री किसानराव पालांडे, विकास विभाग की उप आयुक्त श्रीमती स्मिता काले, वैद्यकीय स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. प्रशांत जवड़े, विद्युत कार्यकारी अभियंता श्री प्रवीन गाडे, संयुक्त आयुक्त श्रीमती स्वरूपा परुलीकर सहित अनेक अधिकारी एवं कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

मध्य रेलवे के सोलापुर मंडल में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया

सोलापुर। मध्य रेलवे के सोलापुर मंडल में 11 मार्च 2026 को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस बड़े उत्साह और गर्व के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सोलापुर में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मंडल की महिला कर्मचारियों के अमूल्य योगदान को सम्मानित किया गया।

सोलापुर मंडल के अतिरिक्त मंडल रेल प्रबंधक (एडीआरएम) श्री अंशुमाली कुमार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। अपने संबोधन में उन्होंने रेलवे में कार्यरत महिला कर्मचारियों के उल्लेखनीय योगदान की सराहना की और कहा कि भारतीय रेल सहित विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी और उपलब्धियां लगातार बढ़ रही हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि महिला कर्मचारी अपने समर्पण और पेशेवर दक्षता के माध्यम से संगठन को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

कार्यक्रम में सोलापुर जिला राज्य आबकारी विभाग की अधीक्षक श्रीमती भाग्यश्री जाधव विशेष अतिथि और मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहीं। 'महिला सशक्तिकरण' विषय पर अपने विचार व्यक्त करते हुए उन्होंने महिलाओं को सशक्त बनाने, समाज में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका तथा कार्यस्थलों पर उनकी बढ़ती भागीदारी और नेतृत्व पर महत्वपूर्ण विचार साझा किए।

इस अवसर को यादगार बनाने के लिए मंडल में कई गतिविधियों का आयोजन किया गया। 7 मार्च 2026 को आयोजित खेल प्रतियोगिताओं के विजेताओं को कार्यक्रम के दौरान नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। 11 मार्च 2026 को आयोजित नृत्य प्रतियोगिता के विजेताओं को भी नकद पुरस्कार प्रदान किए गए, जिससे कार्यक्रम में उत्साह और बढ़ गया।

इस अवसर पर सोलापुर मंडल की तीन महिला कर्मचारियों को, जिन्हें जोन स्तर पर 'सशक्त नारी पुरस्कार' के लिए चयनित किया गया था, उनके उत्कृष्ट कार्य और समर्पण के लिए पदक और प्रशंसा-पत्र देकर सम्मानित किया गया। साथ ही प्रोत्साहन स्वरूप मंडल की सभी महिला कर्मचारियों को उपहार भी वितरित किए गए।

कार्यक्रम में केंद्रीय रेलवे महिला कल्याण संगठन, सोलापुर मंडल की अध्यक्ष श्रीमती निभा कुमारी तथा संगठन की अन्य पदाधिकारी और सदस्य भी उपस्थित रहीं। इसके अलावा मंडल के विभिन्न विभागों के शाखा अधिकारी, कर्मचारी, मान्यता प्राप्त यूनियन और संघों के प्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में महिला कर्मचारी कार्यक्रम में शामिल हुईं।

यह कार्यक्रम कर्मचारी कल्याण निधि समिति द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें सोलापुर मंडल के विभिन्न विभागों का सक्रिय सहयोग रहा और इसी के साथ अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2026 का यह आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।

सरकारी मेडिकल कॉलेजों में बाहर की दवाइयाँ लिखने पर होगी कड़ी कार्रवाई- चिकित्सा शिक्षा मंत्री हसन मुश्रीफ

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मुंबई। सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में दवाइयों का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। यदि मरीजों को बाहर से दवाइयाँ खरीदने के लिए लिखा गया तो संबंधित लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ऐसा चिकित्सा शिक्षा मंत्री हसन मुश्रीफ ने विधान परिषद में प्रश्नकाल के दौरान स्पष्ट किया।

सदस्य अमोल मिटकरी ने अकोला के सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में मरीजों को दवाइयाँ उपलब्ध कराने के संबंध में प्रश्न उठाया था।

इस पर जवाब देते हुए चिकित्सा शिक्षा मंत्री हसन मुश्रीफ ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में उपचार के लिए बड़ी संख्या में मरीज आते हैं। इन मरीजों को आवश्यक दवाइयाँ उपलब्ध हों, इसके लिए अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में दवाइयों का भंडार रखा जाता है। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में दवाइयों की खरीद के लिए एक निर्धारित प्रक्रिया है। उन्होंने बताया कि दवाइयों की खरीद के लिए मिलने वाले कुल निधि में से लगभग 70 प्रतिशत दवाइयाँ खरीद प्राधिकरण के माध्यम से खरीदी जाती हैं, जबकि शेष 30 प्रतिशत राशि संबंधित संस्थानों द्वारा खर्च की जाती है। इसके अलावा जिला नियोजन समिति से प्राप्त निधि से भी आवश्यक दवाइयाँ खरीदी जाती हैं।

मंत्री मुश्रीफ ने कहा कि अकोला के सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के संबंध में सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों को गंभीरता से लिया जाएगा। इस मामले में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निरीक्षण कर रिपोर्ट ली जाएगी।

उन्होंने यह भी बताया कि इस अस्पताल में एमआरआई और सीटी स्कैन जैसी जांच की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही सरकार ने सरकारी अस्पतालों में जन-निजी भागीदारी के आधार पर नई व्यवस्था शुरू करने का भी निर्णय लिया है।

गुजरात की तर्ज पर राज्य में आधुनिक 'बस पोर्ट' बनाए जाएंगे, एसटी डिपो के विकास को मिलेगी गति - परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक

मुंबई। राज्य में गुजरात की तर्ज पर आधुनिक 'बस पोर्ट' विकसित करने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। साथ ही राज्य परिवहन महामंडल के डिपो और बस स्टैंड के समग्र विकास के लिए नई नीति तैयार की गई है, ऐसी जानकारी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने विधान परिषद में दी।

विधान परिषद में नियम 92 के अंतर्गत सदस्य प्रवीण दरेकर ने इस विषय पर आधे घंटे की चर्चा प्रस्तुत की थी।

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार के मार्गदर्शन में राज्य में आधुनिक यात्री सुविधाओं से सुसज्जित एसटी बस स्टैंड विकसित किए जाएंगे।

उन्होंने बताया कि राज्य के एसटी बस स्टेशनों और डिपो के वाणिज्यिक आधार पर विकास परियोजनाओं के लिए लीज समझौते की अवधि 49 वर्ष अर्थात 98 वर्ष रखने का प्रावधान किया गया है। इससे निवेशकों को परियोजनाओं को लागू करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और एसटी महामंडल को दीर्घकालीन वित्तीय आय प्राप्त होगी।

इन परियोजनाओं के माध्यम से यात्रियों को स्वच्छ, सुरक्षित और आधुनिक सुविधाएँ उपलब्ध होंगी। साथ ही स्थानीय युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार और व्यापार के अवसर भी सृजित होंगे। मंत्री सरनाईक ने कहा कि इस परियोजना के अंतर्गत केवल शहरी क्षेत्रों पर ही नहीं बल्कि संतुलित विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके लिए तीन डिपो का एक पैकेज तैयार किया जाएगा, जिसमें एक डिपो शहरी क्षेत्र में, एक डिपो तालुका स्तर पर और एक डिपो ग्रामीण क्षेत्र में होगा। इसके बाद निविदा प्रक्रिया लागू की जाएगी।

इस पहल से ग्रामीण क्षेत्रों के बस स्टैंडों का भी विकास संभव हो सकेगा।

हड़ताल समाप्त कर श्रमिकों को तत्काल काम पर लें - श्रम मंत्री आकाश फुंडकर के निर्देश

मुंबई।श्रम मंत्री अधिवक्ता आकाश फुंडकर ने टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ इंडिया लिमिटेड (धनिवली, तालुका मुरबाड, जिला ठाणे) के परिधान विभाग के कर्मचारियों द्वारा की जा रही हड़ताल का समाधान निकालने तथा निलंबित श्रमिकों को तुरंत काम पर लेने के निर्देश कंपनी प्रबंधन को दिए हैं। साथ ही क्षेत्र में शांति बनाए रखने पर भी जोर दिया गया है। इस संबंध में मंत्रालय में कंपनी के कर्मचारियों के मुद्दों पर एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें श्रम मंत्री फुंडकर बोल रहे थे। बैठक में मुरबाड के विधायक किसान कथोरे, श्रम विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आई. ए. कुंदन, श्रम आयुक्त एच. पी. तुम्मोड, उप श्रम आयुक्त संभाजी वनाळकर, अतिरिक्त श्रम आयुक्त भगवान आंधळे, सहायक श्रम आयुक्त अनघा क्षीरसागर तथा कंपनी के निदेशक सुदर्शन सराफ उपस्थित थे। श्रम मंत्री अधिवक्ता आकाश फुंडकर ने कहा कि टेक्नोक्राफ्ट कंपनी के परिधान विभाग के कर्मचारी 1 दिसंबर 2025 से हड़ताल पर हैं। इस स्थिति का शीघ्र समाधान निकालना आवश्यक है। कर्मचारियों की मांगों को ध्यान में रखते हुए मानवीय दृष्टिकोण से निर्णय लेने की आवश्यकता है। ऐसे में कंपनी के निदेशक मंडल को श्रमिकों और कंपनी दोनों के हितों को ध्यान में रखते हुए संतुलित और सकारात्मक निर्णय लेना चाहिए। उन्होंने स्थायी और संविदा श्रमिकों की समस्याओं को समझकर उनका उचित समाधान करने पर भी जोर दिया।

सम्पादकीय

भारतीय रसोईघर तक आई ईरान-इजरायल युद्ध की आंच, क्या फिर से खत्म होने वाली है आपकी रसोई गैस?

दुनिया भर में युद्ध सैन्य मोर्चों पर लड़े जाते रहे हैं, लेकिन उसकी आंच में आम लोग झुलसते हैं। ईरान पर इजराइल और अमेरिका के साझा हमले के बाद इस युद्ध का दायरा जिस स्वरूप में फैला है, उसका असर अब आशंका के अनुरूप सामने आना शुरू हो चुका है।समस्या यह है कि दुनिया के ज्यादातर देश आमतौर पर हर समय इतनी पूर्व-सावधानी नहीं बरतते हैं कि युद्ध से उपजी आपात स्थिति से निपटने के लिए जरूरी उपायों को लेकर अपनी ओर से अगले कई महीनों के लिए पूरी तैयारी रखें। कई बार अचानक पैदा होने वाले हालात में पहले आपूर्ति का मोर्चा बाधित होता है।

उसके बाद आम लोगों के जीवन-बसर के लिए अनिवार्य चीजों की कमी शुरू हो जाती है और फिर उसका असर बाहर भी दिखने लगता है, जिसमें लोगों के बीच रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने की समस्या को लेकर चिंता ज्यादा बढ़ जाती है। इजराइल और अमेरिका के ईरान पर हमले के दस दिन बाद कई देशों में लगभग यही स्थिति बन रही है।

जहां तक भारत का सवाल है, तो जब से ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य के रास्ते को रोका है, तब से तेल टैंकरों की आवाजाही और गैस की आपूर्ति भी व्यापक रूप से बाधित हुई है। इसके अलावा, ईरान ने जवाबी हमले के तौर पर जिस तरह खाड़ी के कई देशों के तेल रिफाइनरियों पर हमले किए, उसके बाद कच्चे तेल का संकट ज्यादा गहरा गया है।

हालांकि होर्मुज मार्ग पर ईरान के रुख के बाद यह साफ हो गया था कि अगर यह युद्ध थोड़ा लंबा खिंचा, तो दुनिया के कई देश इससे बुरी तरह प्रभावित होंगे। तेल और गैस के अभाव की वजह से न सिर्फ आम जनजीवन में अफरा-तफरी पैदा होगी, बल्कि बड़े पैमाने पर आर्थिक संकट खड़ा होगा। इसी क्रम में भारत में अब यह साफ दिखने लगा है कि अगर सरकार की ओर से जल्दी ही कोई उपयुक्त कदम नहीं उठाए गए, तो स्थिति जटिल हो सकती है।

दरअसल, युद्ध की आंच अब भारत में रसोईघरों और व्यापार तक पहुंचनी शुरू हो गई है। एलएनजी यानी तरल प्राकृतिक गैस और एलपीजी यानी तरल पेट्रोलियम गैस के मामले में भारत आमतौर पर आयात पर निर्भर रहा है। यही वजह है कि होर्मुज समुद्री रास्ते से तेल टैंकरों की आवाजाही बाधित होने के बाद भारत में अब एलपीजी की किल्लत का खतरा मंडराने लगा है और कई राज्यों में रेस्तरां तथा होटलों को वाणिज्यिक एलपीजी की आपूर्ति में मुश्किल शुरू हो गई है।

साथ ही बाजार में खाने-पीने की चीजों से लेकर अन्य सामान की कीमतों में इजाफे की रफ्तार तेज हो गई है। असली समस्या रसोई गैस और अन्य सामान की आपूर्ति है, जिसमें भारी कमी की वजह से लोगों के बीच अफरा-तफरी का माहौल बन रहा है। हालत यह है कि आने वाले दिनों में संकट गहराने की आशंका से ज्यादातर लोग एहतियातन एलपीजी सहित अन्य सामान लेने के लिए कतारों में खड़े दिखने लगे हैं।

एक ओर, जरूरत से ज्यादा खरीदारी और दूसरी ओर कारोबारियों की अवैध जमाखोरी या भंडारण की वजह से कालाबाजारी और महंगाई जैसे संकट के मद्देनजर सरकार को आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू करना पड़ा है। मगर यह सुनिश्चित करना भी सरकार की जिम्मेदारी है कि रसोई गैस या परिवहन इस हद तक नियंत्रित न हों कि इससे रोजमर्रा की अनिवार्य गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।यह भी देखने की जरूरत होगी कि अगर जरूरी वस्तुओं की कमी का संकट गहराया, तो वैकल्पिक स्रोतों से उसे कैसे पूरा किया जाएगा।

मुहम्मद यूनुस दौर के बाद बदली बांग्लादेश की विदेश नीति पीएम तारिक रहमान ने भारत के साथ बढ़ाया सहयोग

बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद युनूस के समय कई बार यह देखने को मिला कि वह भारत के विरोधियों और कट्टरपंथी ताकतों के करीब नजर आते थे। उस दौर में बांग्लादेश की विदेश नीति को लेकर नई चिंताएं भी सामने आई थीं और कई नेता तथा अधिकारी पाकिस्तान का दौरा करते दिखाई देते थे। लेकिन अब हालात बदलते दिख रहे हैं। नई सरकार के प्रधानमंत्री तारिक रहमान यह अच्छी तरह समझते हैं कि भारत के साथ मजबूत संबंध बांग्लादेश की स्थिरता, सुरक्षा और आर्थिक विकास के लिए बेहद जरूरी हैं। इसी कारण उन्होंने विदेश नीति में संतुलन लाते हुए भारत के साथ संबंध सुधारने की दिशा में सक्रिय कदम उठाने शुरू कर दिए हैं।

भारत और बांग्लादेश के संबंध अब एक नए चरण में प्रवेश करते दिख रहे हैं। नई सरकार बनने के बाद दोनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग, खुफिया जानकारी के आदान प्रदान और ऊर्जा क्षेत्र में सहायता को लेकर तेजी से गतिविधियां बढ़ी हैं। मार्च की शुरुआत में बांग्लादेश की प्रमुख रक्षा खुफिया एजेंसी के प्रमुख का भारत दौरा इसी बदलते कूटनीतिक माहौल का महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है।

सूत्रों के अनुसार बांग्लादेश की रक्षा खुफिया एजेंसी के महानिदेशक मेजर जनरल कैसर रशीद चौधरी ने एक से तीन मार्च के बीच दिल्ली का दौरा किया। यह दौरा उस समय हुआ जब बांग्लादेश में चुनाव के बाद तारिक

रहमान ने प्रधानमंत्री पद संभाला है। प्रधानमंत्री बनने के कुछ ही दिन बाद उन्होंने कैसर रशीद को पदोन्नति देकर इस महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया था।

दिल्ली में अपने दौरे के दौरान मेजर जनरल चौधरी ने भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी के प्रमुख पराग जैन और सैन्य खुफिया महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल आर एस रमन से मुलाकात की। दो मार्च को एक निजी रात्रि भोजन के दौरान दोनों देशों के खुफिया प्रमुखों के बीच विस्तृत चर्चा हुई। इसमें सुरक्षा सहयोग, खुफिया जानकारी के साझा उपयोग और सीमापार गतिविधियों को रोकने के उपायों पर विचार किया गया।

हम आपको बता दें कि भारत लंबे समय से बांग्लादेश की जमीन से चल रही भारत विरोधी गतिविधियों को लेकर सतर्क रहा है। इसलिए नई सरकार के साथ सुरक्षा सहयोग बढ़ाना दिल्ली की प्राथमिकता माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अंतरिम सरकार के दौरान कानून व्यवस्था की स्थिति कुछ कमजोर हुई थी और इसी कारण सुरक्षा सहयोग को मजबूत करना दोनों देशों के हित में है।

बांग्लादेश में पिछले वर्ष छात्र आंदोलन के बाद राजनीतिक अस्थिरता देखी गई थी। इसी दौर में युवा नेता शरीफ उस्मान बिन हादी की हत्या ने देश में तनाव और विरोध प्रदर्शनों को बढ़ा दिया था। दिसंबर में ढाका में उन पर हमला हुआ था और बाद में सिंगापुर के एक अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई थी। हाल ही में पश्चिम बंगाल के बोंगांव क्षेत्र से इस हत्या मामले में दो बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा गया है। इसके बाद बांग्लादेश सरकार ने इन आरोपियों से दूतावास संपर्क की मांग भी की है।

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार नई सरकार का भारत के साथ सहयोग बढ़ाना क्षेत्रीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण संकेत है। अंतरिम सरकार के समय कई बार बांग्लादेश के नेता और अधिकारी पाकिस्तान का दौरा किया करते थे, जिससे क्षेत्रीय संतुलन को लेकर चिंताएं भी सामने आई थीं। लेकिन नई सरकार को यह समझ है कि भारत के साथ घनिष्ठ संबंध आर्थिक विकास, सुरक्षा और स्थिरता के लिए अत्यंत जरूरी हैं। यही कारण है कि अब बांग्लादेश के अधिकारी भारत के साथ संवाद और सहयोग को प्राथमिकता दे रहे हैं।

इसी बीच, ऊर्जा क्षेत्र में भी भारत ने बांग्लादेश की मदद कर अपने भरोसेमंद मित्र होने का परिचय दिया है। ईरान युद्ध के कारण वैश्विक तेल आपूर्ति प्रभावित होने से बांग्लादेश को ईंधन संकट का सामना करना पड़ रहा है। इस कठिन समय में भारत ने पांच हजार टन डीजल की खेप बांग्लादेश को भेजी है। यह आपूर्ति दोनों देशों के बीच चल रहे ऊर्जा समझौते के तहत की गई है।

हम आपको बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच भारत बांग्लादेश मित्रता पाइपलाइन परियोजना के माध्यम से हर वर्ष एक लाख अस्सी हजार टन डीजल आपूर्ति का प्रावधान है। यह डीजल असम के नुमालिगड तेल शोधन कारखाने से भेजा जाता है। वर्तमान संकट को देखते हुए बांग्लादेश ने अतिरिक्त आपूर्ति का अनुरोध भी किया है, जिस पर भारत उपलब्धता और बाजार स्थिति के अनुसार विचार कर सकता है।

दूसरी ओर, ऊर्जा संकट से निपटने के लिए बांग्लादेश सरकार ने कई सख्त कदम उठाए हैं। देश में ईंधन की बिक्री पर दैनिक सीमा लगाई गई है और आपूर्ति संतुलन बनाए रखने के लिए विश्वविद्यालयों को भी अस्थायी रूप से बंद किया गया है। देखा जाये तो बांग्लादेश को भारत की यह सहायता केवल व्यापारिक समझौते का हिस्सा भर नहीं है, बल्कि यह उसकी उस नीति को भी दर्शाती है जिसमें वह पड़ोसी देशों की कठिन समय में बिना स्वार्थ सहायता करता रहा है। नेपाल में आपदा, श्रीलंका में आर्थिक संकट या बांग्लादेश में ऊर्जा कमी जैसे कई अवसरों पर भारत ने त्वरित मदद देकर क्षेत्रीय सहयोग का उदाहरण प्रस्तुत किया है।

सामरिक दृष्टि से भी भारत बांग्लादेश सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोनों देशों की लंबी सीमा है और पूर्वोत्तर भारत की सुरक्षा तथा आर्थिक विकास काफी हद तक बांग्लादेश के साथ स्थिर संबंधों पर निर्भर करता है। मजबूत खुफिया सहयोग से उग्रवाद, अवैध तस्करी और सीमा पार अपराधों को रोकने में मदद मिलती है। वहीं ऊर्जा और व्यापार सहयोग से दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को लाभ मिलता है।

कुल मिलाकर देखें तो यह स्पष्ट है कि भारत और बांग्लादेश के संबंध एक नए विश्वास और साझेदारी की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सुरक्षा सहयोग, ऊर्जा सहायता और पारस्परिक सम्मान पर आधारित यह संबंध आने वाले समय में पूरे दक्षिण एशिया की स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं।

कहीं जिम्मेदारियों के बोझ तले दम तो नहीं तोड़ रहे आपके सपने?

जिंदगी में हम हमेशा कुछ न कुछ चाहने की आदत में बंधे रहते हैं। यह चाहत ही शायद हमें इंसान बनाती है, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। कभी ये इच्छाएं छोटी होती हैं, जैसे किसी अपने की मुस्कान, किसी परीक्षा में सफलता, या एक सुकून भरी शाम और कभी बहुत बड़ी जैसे एक बेहतर भविष्य, पहचान, सम्मान और अपने सपनों की उड़ान। मगर हर इच्छा, हर ख्वाब हमें आगे बढ़ने की ताकत देते हैं।

जब हम अपनी आंखों में ख्वाब संजोते हैं, तो वह ख्वाब हमें इस दुनिया के हर कोने में कुछ नया खोजने की प्रेरणा देता है। इन्हीं ख्वाबों के सहारे हम अपने जीवन के भविष्य के महल मन ही मन बना लेते हैं, मानो हर मंजिल हमारी मुट्ठी में हो। उस समय हमें लगता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी पा सकते हैं, लेकिन क्या कभी हमने ठहरकर यह सोचा है कि इन ख्वाबों को पूरा करने का रास्ता उतना आसान नहीं होता, जितना हमें शुरुआत में लगता है?

शुरुआत में हर ख्वाब हमें अपना-सा लगता है। वे ख्वाब हमारे मन में इतने गहरे बैठ जाते हैं कि हमें लगता है जैसे वे हमारी ही दुनिया हों। हर मंजिल हमसे बस कुछ कदमों की दूरी पर दिखाई देती है। हम ख्वाबों के रंगीन संसार में खो जाते हैं, जहां सब कुछ सुंदर होता है, सरल होता है। हम यह मान लेते हैं कि मेहनत करेंगे तो सब मिल जाएगा, कि हर बाधा को हम आसानी से पार कर लेंगे। उस समय हमारे भीतर आत्मविश्वास होता है, जोश होता है और भविष्य के प्रति एक अटूट विश्वास होता है, लेकिन जैसे-जैसे वक्त गुजरता है, हम हकीकत का सामना करने लगते हैं।

हकीकत की ठोकरें हमें हमारे ख्वाबों की असली कीमत समझाने लगती हैं। जिन रास्तों पर हमने फूलों की कल्पना की थी, उन्हीं रास्तों पर कांटे उग आते हैं। असफलताएं हमें घेर लेती हैं और हमारी उम्मीदें धीरे-धीरे फीकी पड़ने लगती हैं। ऐसा आमतौर पर होता है कि जब कोई चीज हमें आसानी से मिल जाती है, तो हम उसकी कीमत समझने की कोशिश नहीं करते। इसी तरह, अगर कोई व्यक्ति हमसे विनम्र और सद्भावपूर्ण व्यवहार करता है, हमें अपनी बात रखने या अपनी पसंद से आचरण करने की जगह मिलने पर कोई आपत्ति नहीं करता, तो हम वैसे व्यक्ति को हल्का मानकर उसकी अनदेखी करते हैं या उसे कम करके आंकते हैं।

मगर यही जब हमारे व्यक्तित्व में घुल जाता है, तब हम ऐसे व्यवहार की आदी हो जाते हैं और हमारे भीतर एक विचित्र अहं अपने पांव पसारने लगता है। हमें इसका भान तब होता है, जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं और उसकी

कद्र करते हैं और वह हमें कोई महत्त्व नहीं देता। दरअसल, बात यहां यह है कि हमें दूसरों के प्रति ही वैसा व्यवहार करना चाहिए, उसकी कद्र करनी चाहिए, जो हम अपने लिए दूसरों से अपेक्षा करते हैं। वक्त का पहिया कभी रुकता नहीं। यह बिना किसी से पूछे हमें आगे धकेलता रहता है।

इस रफ्तार में हम अक्सर अपने ख्वाबों को पीछे छोड़ देते हैं। हमें लगने लगता है कि दुनिया के साथ चलने के लिए हमें अपने सपनों से समझौता करना पड़ेगा। जिम्मेदारियों और कर्तव्यों का बोझ हमारे कंधों पर इतना बढ़ जाता है कि हम खुद के लिए समय निकालना ही भूल जाते हैं। परिवार, समाज और परिस्थितियों की अपेक्षाएं हमें जकड़ लेती हैं। धीरे-धीरे हम अपने भीतर के उस इंसान से दूर हो जाते हैं, जो कभी बड़े सपने देखा करता था। वक्त की इस अंधी दौड़ में हम यह भूल जाते हैं कि एक समय था जब हमारे ख्वाब हमारे जीने का कारण हुआ करते थे।

फिर किसी एक शाम, जब हम अकेले होते हैं और जिंदगी की रफ्तार कुछ धीमी पड़ जाती है, तब अचानक हमारे भीतर कहीं कोई आवाज गूंजने लगती है। यह आवाज हमारे उन्हीं ख्वाबों की होती है, जो कभी हमारी आंखों में चमक बन कर बसे थे। जब कोई ठंडी हवा चेहरे को छूती है और हम अपनी जिंदगी के बीते वर्षों को याद करते हैं, तो दिल के किसी कोने से एक सवाल उठता है- 'क्या हुआ उन ख्वाबों का, जो कभी तुम्हारी आंखों में उम्मीदों की तरह चमकते थे?' यह सवाल हमें बेचैन कर देता है। हमें एहसास होता है कि कहीं न कहीं हमने अपने ख्वाबों को रास्ते में ही छोड़ दिया है।

जिंदगी की दौड़ में हम बहुत-सी चीजों को खो देते हैं। हम अपने शौक, अपनी मासूम इच्छाएं, और कभी-कभी अपनी पहचान भी खो बैठते हैं। दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करते-करते हम खुद की अपेक्षाओं को दबा देते हैं, लेकिन यह बेहद जरूरी है कि हम खुद को पूरी तरह से बदलने न दें। कभी इतना न बदल जाएं कि हम अपने असली ख्वाबों को ही भूल जाएं, क्योंकि यही ख्वाब थे, जिन्होंने हमें एक दिशा दी थी, जिन्होंने हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी थी। अगर हम अपने ख्वाबों को मरने देंगे, तो हम धीरे-धीरे अपनी असल पहचान भी खो देंगे।

सपने हमें जीने की वजह देते हैं। वे हमें हर गिरावट के बाद उठने की ताकत प्रदान करते हैं। यह सच है कि ख्वाबों की राह आसान नहीं होती। इस राह में असफलताएं आती हैं, निराशा मिलती है, और कई बार खुद पर भी शक होने लगता है। मगर इन्हीं मुश्किलों से गुजर कर सपने साकार होते हैं। संघर्ष के बिना कोई भी सपना सच नहीं होता। जरूरी यह नहीं है कि हम हर ख्वाब पूरा कर ही लें, जरूरी यह है कि हम उन्हें जिंदा रखें।

नौकरी तो मिल रही है, पर क्या वह 'क्वालिटी' वाली है? नीति आयोग की रिपोर्ट ने खोली सेवा क्षेत्र की पोल!

अर्थव्यवस्था के मुख्य रूप से तीन क्षेत्र होते हैं। पहला प्राथमिक क्षेत्र, जिसके अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण और उत्पादन से संबंधित क्रियाएं होती हैं। जैसे कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, वनस्पति और वन उत्पाद और खनन। दूसरा क्षेत्र है जिसमें प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्चे माल से विभिन्न उत्पादों का निर्माण किया जाता है। इसमें विनिर्माण उद्योग, निर्माण कार्य और बिजली उत्पादन जैसी गतिविधियों को सम्मिलित किया जाता है।

अर्थव्यवस्था का तीसरा क्षेत्र सेवाओं से संबंधित है। इसमें व्यापार और वाणिज्य, साजो-समान परिवहन, संचार, शिक्षा और स्वास्थ्य, वित्त, बीमा, पर्यटन तथा आतिथ्य से जुड़ी सेवाओं को शामिल किया जाता है। इन तीनों क्षेत्रों का एक दूसरे से गहरा संबंध है और ये मिल कर देश की अर्थव्यवस्था को आकार देते हैं। रोजगार की दृष्टि से भी ये तीनों क्षेत्र महत्त्वपूर्ण हैं।

भारत का सेवा क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है। इसमें पर्याप्त रोजगार भी उपलब्ध हुए हैं, लेकिन इनमें गुणवत्ता वाले रोजगार की कमी बनी हुई है। सेवा क्षेत्र लगभग 18.8 करोड़ लोगों को रोजगार दे रहा है, जो कुल कार्यबल का लगभग 30 फीसद है। नीति आयोग की एक नई रपट के अनुसार, वर्ष 2023-2024 में सेवा क्षेत्र में रोजगार बढ़ कर 29.7 फीसद हो गया, जो वर्ष 2011-12 में 26.9 फीसद था। इस दौरान लगभग चार करोड़ नौकरियां जुड़ीं जो वैश्विक औसत 50 फीसद से काफी कम है।

इससे संकेत मिलता है कि भारतीय कृषि और सेवा क्षेत्र की बढ़त अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में धीमी रही है। जाहिर है कि सामाजिक सुरक्षा, असंगठित क्षेत्र के पंजीकरण और औपचारिक सेवाओं के विस्तार पर जोर देना होगा। भारत सरकार ने सेवा क्षेत्र को अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा क्षेत्र मानते हुए इसे बढ़ावा देने वास्ते कई महत्त्वपूर्ण प्रयास किए हैं। 'डिजिटल इंडिया अभियान' के अंतर्गत कई सरकारी सेवाओं को आनलाइन किया गया है।

डिजिटल भुगतान और ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने के प्रयास किए गए और ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट सुविधा का विस्तार करने के लिए कदम उठाए गए। 'स्टार्टअप इंडिया योजना' के अंतर्गत नए उद्यमों को करों में छूट और पंजीकरण प्रक्रिया को आसान किया गया है। जो कंपनियां नवाचार और सेवा आधारित कार्यों को प्रोत्साहन देती हैं, उनको कई राहत और प्रोत्साहन देने की घोषणाएं की है। 'मेक इन इंडिया अभियान' के अंतर्गत विनिर्माण के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यटन और आतिथ्य जैसे सेवा क्षेत्रों को बढ़ावा देने के उपाय किए गए हैं।

इसके अलावा, 'स्किल इंडिया मिशन' के माध्यम से युवाओं को तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर सेवा क्षेत्र के लिए कुशल कार्यबल तैयार करने की योजनाएं बनाई गई हैं। साथ ही पर्यटन स्थलों का विकास और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के प्रयास किए गए हैं। होटल और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न स्तरों पर कोशिश जारी हैं। आइटी और बीपीओ क्षेत्र को प्रोत्साहन, साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना, सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों को कर रियायतें और सेवा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं बनाई गई हैं।

सरकार ने वित्तीय समावेशन योजनाओं के अंतर्गत बैंकिंग सेवाओं का विस्तार और डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के भी उपाय किए हैं। हकीकत यह है कि सरकारी प्रोत्साहनों और प्रयासों के बावजूद सेवा क्षेत्र की अधिकांश नौकरियां और सेवाएं अभी भी कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों जैसे व्यापार और परिवहन में केंद्रित है, जबकि सूचना प्रौद्योगिकी, वित्त, स्वास्थ्य और व्यावसायिक सेवाएं अधिक मूल्य सृजन तो करती हैं, लेकिन इनमें रोजगार के अवसर सीमित हैं। नीति आयोग के अनुसार, सेवा क्षेत्र अब भारत की आर्थिक वृद्धि की रीढ़ बन गया है। हालांकि, ग्रामीण और शहरी असमानताएं अभी भी बनी हुई हैं।

गुणवत्ता वाला रोजगार वह होता है, जिसमें काम के बदले पर्याप्त आय मिले, जो जीवनयापन की जरूरतों को पूरा करे। यह समय पर भी मिले। शारीरिक और मानसिक रूप से सुरक्षित कार्यस्थल हो जो स्वास्थ्य जोखिम एवं भेदभाव जैसे उत्पीड़न तथा असुरक्षित कार्य से मुक्त हो। चिकित्सा बीमा, पेंशन, भविष्य निधि, मातृत्व लाभ और वेतन सहित छुट्टियां जैसी सुविधाएं मिलें। व्यक्ति के कौशल विकास, प्रशिक्षण, पदोन्नति और आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध हों। यदि हम इन मापदंडों के आधार पर सेवा क्षेत्र का मूल्यांकन करें, तो पाते हैं कि अधिकांश सेवा क्षेत्र उपक्रमों में इन आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जाता।

सेवा क्षेत्र में रोजगार की गुणवत्ता की दृष्टि से अधिकांश सेवा क्षेत्र उपक्रमों में असमानता है और गुणवत्ता की शर्तें लागू नहीं होतीं। इसमें अधिकांश रोजगार अनौपचारिक और कम वेतन वाले हैं। सेवा क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की भागीदारी कम है।

सेवा क्षेत्र में रोजगार की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। इसके लिए व्यावहारिक कार्यक्रमों और नीतियों को लागू करना जरूरी है। इस क्षेत्र की जो गतिविधियां अनौपचारिक क्षेत्र में हैं, उनको औपचारिक क्षेत्र में लाने और कार्यरत व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रयास करना जरूरी हैं।

महिलाओं और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए कौशल विकास और डिजिटल माध्यमों की पहुंच बढ़ाना भी आवश्यक है। इसमें निवेश और नवाचार भी बढ़ाने की जरूरत है। इसमें कार्यरत श्रम बल के रोजगार की गुणवत्ता की दृष्टि से कई उपाय किए जा सकते हैं, जिनमें स्व-नियोजित व्यक्ति और सूक्ष्म लघु तथा मध्यम क्षेत्र के उपक्रमों के श्रमिकों के लिए औपचारिक रोजगार एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाएं लागू करने, ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल तथा डिजिटल पहुंच पर ध्यान केंद्रित करना जरूरी है। शहरों में सेवा केंद्रों के माध्यम से संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा दिया जाना भी जरूरी है। इससे रोजगार में गुणवत्ता बनी रह सकती है।

रोजगार गुणवत्ता की दृष्टि से डिजिटल अवसंरचना, नवाचार, वित्त और कौशल को प्राथमिकता, स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर राज्य स्तरीय सेवा रणनीति विकसित करना, संस्थागत क्षमता में सुधार और सेवाओं को औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र के साथ संतुलित करना एवं प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए शहरी और क्षेत्रीय सेवा समूहों का विस्तार जैसे उपाय भी किए जा सकते हैं। सेवा क्षेत्र को बढ़ावा देने और इस क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों के रोजगार में गुणवत्ता बढ़ाने की दृष्टि से जहां एक तरफ सरकारी उपाय जरूरी है, वहीं इस क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों का कौशल बढ़ाने एवं प्रशिक्षण संस्थानों को कुशल कार्यबल उपलब्ध कराने के लिए गुणवत्ता में सुधार करना जरूरी है।

गुणवत्तापूर्ण रोजगार के लिए जो युवा सेवा क्षेत्र में आना चाहते हैं, उन्हें भी कुछ प्रयास करने होंगे। वे जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उसमें उन्हें प्रशिक्षण लेना चाहिए। व्यावसायिक अनुभव के लिए अपने क्षेत्र से संबंधित व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। सामूहिक भावना और नेतृत्व क्षमता को बढ़ावा देना चाहिए। साथ ही कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और डिजिटल विपणन क्षमता को भी विकसित करने की जरूरत है।

कौशल विकास के लिए सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में कई आनलाइन पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। इनमें से जिस क्षेत्र में युवा अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, उस क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए व्यावहारिक अनुभव लेने का प्रयास करना चाहिए। दो मत नहीं कि सामूहिक प्रयासों से ही सेवा क्षेत्र में रोजगार की गुणवत्ता बढ़ाई जा सकती है।

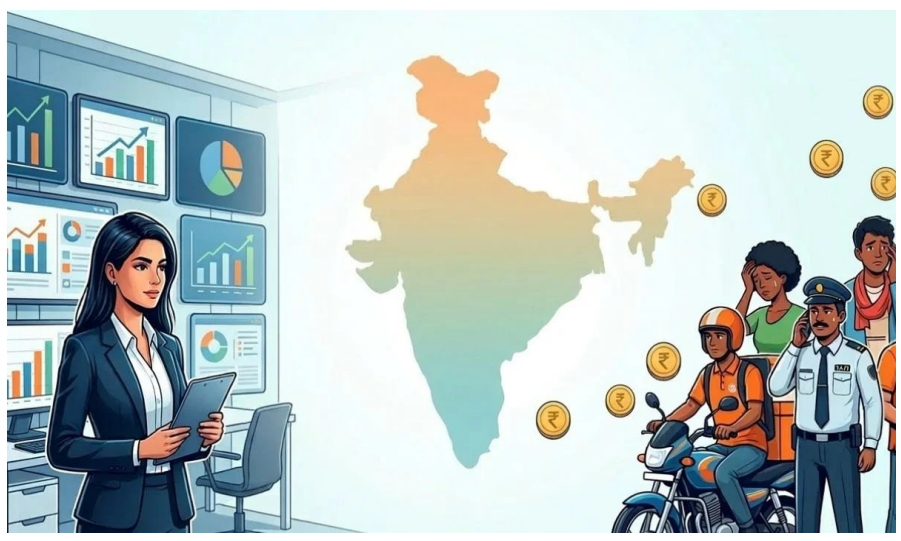

एकजुट के प्रदेश संरक्षक ने यूपी बोर्ड परीक्षा संपन्न होने पर बोर्ड सचिव को दी बधाई

ईद के बाद शुरू कराया जाय मूल्यांकन : डा हरि प्रकाश यादव

समस्याओं का शीघ्र निस्तारण होगा : सचिव भगवती सिंह

मंत्र भारत संवाददाता

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (एकजुट) के प्रदेश संरक्षक डा हरि प्रकाश यादव ने यूपी बोर्ड परीक्षा सकुशल संपन्न होने पर बोर्ड सचिव भगवती सिंह को आज यूपी बोर्ड मुख्यालय में बधाई दिया। इस दौरान एकजुट के प्रदेश संरक्षक डा हरि प्रकाश यादव ने सचिव भगवती सिंह को ज्ञापन सौंपा जिसमें मांग की गयी है कि यूपी बोर्ड की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन ईद पर्व के पश्चात कराया जाये।

एकजुट के ज्ञापन मे कहां गया है कि कापियों का 18 मार्च से मूल्यांकन कार्य होने जा रहा है, जबकि शिक्षा निदेशक माध्यमिक द्वारा जारी अवकाश कैलेण्डर में 20 मार्च शुक्रवार को जुमा अलविदा एवं 21 मार्च को ईद उल फितर का सार्वजनिक अवकाश घोषित है परंतु जब मूल्यांकन कार्य होता है तो उस समय कोई अवकाश नहीं दिया जाता है यहां तक कि रविवार को भी काफियों का मूल्यांकन कराया जाता है । होली की तरह ईद भी एक महत्वपूर्ण त्यौहार है, यदि मूल्यांकन 18 मार्च से शुरू होता है तो बीच में ईद पर्व के कारण मूल्यांकन कार्य प्रभावित होगा इसलिए उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन ईद के बाद शुरू कराया जाय।

एकजुट के प्रतिनिधि मंडल ने बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित नाम संशोधन की प्रक्रिया में आ रही व्यावहारिक कठिनाइयों का मुद्दा भी उठाया। संगठन ने बताया कि वर्तमान में नाम संशोधन के लिए टीसी पर काउंटर साइन की अनिवार्यता रखी गई है,जिसके कारण कई बार छात्र - छात्राओं को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। विशेषकर जब छात्र विद्यालय से दूर होते हैं या परीक्षा के बाद अन्य स्थानों पर चले जाते हैं, तब काउंटर शाइन कराना कठिन हो जाता है। इस कारण कई छात्रों के नाम संशोधन के प्रकरण समय पर पूर्ण नहीं हो पाते। एकजुट शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने सचिव से अनुरोध किया कि छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए इस प्रक्रिया को सरल बनाया जाए तथा टीसी प्रति हस्ताक्षर की अनिवार्यता में व्यावहारिक समाधान निकाला जाए, ताकि छात्रों को अनावश्यक परेशानी से बचाया जा सके।

यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने प्रतिनिधिमंडल द्वारा उठाए गए सभी बिंदुओं को गंभीरता से सुना और शीघ्र समस्याओं के निस्तारण का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में परिषद स्तर पर सकारात्मक विचार कर आवश्यक निर्णय लिया जाएगा। इस अवसर पर एकजुट के प्रतिनिधिमंडल में जिला अध्यक्ष देवराज सिंह, प्रदेश आय व्यय निरीक्षक सुरेंद्र प्रताप सिंह, प्रदेश मीडिया प्रभारी सुधाकर ज्ञानार्थी मंडल अध्यक्ष मिथिलेश कुमार मौर्य, जिला मंत्री डीपी यादव सहित संगठन के अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। एकजुट के प्रदेश संरक्षक डा हरि प्रकाश यादव ने आशा व्यक्त किया है कि परिषद शिक्षकों एवं छात्रों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए शीघ्र ही उचित निर्णय लेगी।

बीआरसी जसरा में दो दिवसीय नालेज शेयरिंग कार्यशाला संपन्न

शिक्षकों ने लगाई टीएलएम प्रदर्शनी

प्रयागराज। ब्लाक संसाधन केंद्र जसरा घूरपुर प्रयागराज में दो दिवसीय नालेज शेयरिंग कार्यशाला संपन्न हुई। सत्तर शिक्षकों ने इस दो दिवसीय कार्यशाला में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में खंड शिक्षा अधिकारी अखिलेश वर्मा ने कहा कि नालेज शेयरिंग कार्यक्रम से शिक्षकों के नवाचारों का आदान-प्रदान होता है।ऐसे कार्यक्रम से शिक्षक एक दूसरे से जानकारी, विचार,कौशल और अनुभव का आदान-प्रदान करते हैं।यह शिक्षकों एवं विद्यालयों की गुणवत्ता सुधारने, चुनौतियों का समाधान करने व नवाचार को बढ़ावा देने में मदद करता है। एआरपी श्रीनारायण मिश्र अरविंद सैनी पंकज कुमार साहू महेंद्र निषाद ने विभिन्न सत्रों में इस कार्यशाला को संचालित किया। प्रशिक्षण के दूसरे दिन सभी न्याय पंचायत के शिक्षकों ने अपने न्यायपंचायत के नवाचारों से संबंधित टीएलएम की प्रदर्शनी लगाई।जिसकी सभी ने बहुत प्रशंसा किया। बेहतरीन टीएलएम निर्माण करने वाले शिक्षकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।इस अवसर पर प्रमोद कुमार मिश्र,उमेश शुक्ला,अल्का शर्मा, बुशरा खाऩम,फरहा एजाज, अभिषेक कुमार, जितेन्द्र कुमार शर्मा, बबिता वर्मा, ज्योति जायसवाल, जितेन्द्र मिश्र, सुभाषिनी केसरवानी,सरिता कनौजिया,नीलम सिंह, अंकिता शुक्ला,रिचा मिश्रा,रेखा सिंह,ऊषा यादव आदि शिक्षक उपस्थित रहे।

सात दिवसीय विरासत कला उत्सव का हुआ समापन

छाप तिलक' और 'दमादम मस्त कलंदर' पर झूमे श्रोता, चंचल भारती ने बांधा समां

मंत्र भारत संवाददाता

प्रयागराज। जब सूफियाना सुरों की मिठास और भक्ति की गूंज एक साथ मंच से उठी, तो पूरा प्रेक्षागृह मानो रूहानी एहसास से भर उठा। सुर, साज़ और अल्फ़ाज़ के इसी जादुई संगम के साथ उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित सात दिवसीय 'विरासत कला उत्सव' का गुरुवार को रंगारंग समापन हुआ। प्रसिद्ध क़व्वाल गायिका चंचल भारती ने अपने सूफियाना अंदाज़ और दमदार गायन से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। बनारस घराने से ताल्लुक रखने वाली चंचल भारती ने कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना से की। इसके बाद उन्होंने 'सीता-सीता राम कहिए' की भावपूर्ण प्रस्तुति देकर पूरे प्रेक्षागृह को भक्तिमय वातावरण में सराबोर कर दिया।

इस अवसर पर हिन्दी पखवाड़ा के अंतर्गत आयोजित भाषण एवं निबंध प्रतियोगिता के प्रतिभागियों को स्मृति चिन्ह और प्रमाण-पत्र देकर सम्मानित किया गया। निबंध प्रतियोगिता में कृष्णा मिश्रा प्रथम, गीतांजलि शर्मा द्वितीय और वैष्णवी तृतीय स्थान पर रहीं, जबकि अंकिता पाण्डेय और मीनाक्षी को सांत्वना पुरस्कार प्रदान किया गया। वहीं भाषण प्रतियोगिता में खुशी सेठ प्रथम, शुभम सिंह द्वितीय तथा रागिनी तिवारी तृतीय स्थान पर रहीं, जबकि अलीसा अंसारी और सुहाना को सांत्वना पुरस्कार दिया गया।इस अवसर पर महेश्वर दयाल सहायक आचार्य प्रयाग संगीत समिति, वरिष्ठ रंगकर्मी अभिलाष नारायण, कार्यक्रम प्रभारी कृष्ण मोहन द्विवेदी, मधुकांक मिश्रा सहित केंद्र के सभी अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉ. आकांक्षा पाल ने किया।

मॉडर्न ठेला एवं 10 हजार का चेक पाकर प्रसन्न हुए प्रयागराज के 13 परिवार

वैश्य इंटरनेशनल एसोसिएशन एवं मंत्री नन्दी के सहयोग से पूर्व महापौर अभिलाषा गुप्ता नन्दी ने दिया मॉडर्न ठेला

मंत्र भारत संवाददाता

प्रयागराज। वैश्य समाज के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वैश्य इंटरनेशनल एसोसिएशन एवं औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी के सहयोग से प्रयागराज की पूर्व महापौर श्रीमती अभिलाषा गुप्ता नन्दी द्वारा गुरुवार को चैथम लाइन में प्रयागराज के 13 परिवारों को मॉडर्न ठेला एवं दस हजार रूपए का चेक के साथ ही व्यवसाय की सारी सामग्री प्रदान की गई। वैश्य इंटरनेशनल एसोसिएशन (वाया) वैश्य समाज के लोगों के उत्थान के साथ ही व्यापार एवं उद्योगों के विकास, प्रदेश की आर्थिक उन्नति के लिए प्रयासरत है।

प्रयागराज की पूर्व महापौर श्रीमती अभिलाषा गुप्ता नन्दी ने कहा कि वैश्य समाज सदैव अपने पूर्वजों की गौरवशाली परम्परा, सेवा और संस्कारों को आगे बढ़ाता आया है।

किसी भी व्यापार को करने एवं अपने परिवार का जीविकोपार्जन करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। बैंक के नियमों की श्रेणी में शामिल न हो पाने की वजह से लोग सूदखोरों के चक्कर में फंस जाते हैं और फिर इस दलदल से बाहर निकल नहीं पाते हैं। ऐसे लोगों को सूदखोरों के चंगुल से बचाना, आर्थिक सहायता प्रदान करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना ही वैश्य इंटरनेशनल एसोसिएशन का लक्ष्य है। ताकि वे अपना व्यापार बढ़ाने के साथ ही परिवार का जीविकोपार्जन कर सकें।

लोग सम्मान पूर्वक व्यापार करते हुए अपनी आजीविका चला सकें इसलिए आधुनिक ठेला दिया जा रहा है।

वैश्य इंटरनेशनल एसोसिएशन का उद्देश्य केवल किसी जरूरतमंद की आर्थिक सहायता कर देना भर नहीं है। बल्कि उसे व्यापार से जोड़ कर आत्मनिर्भर बनाना ही लक्ष्य है।

ठेला प्राप्त करने वालों में मुट्ठीगंज निवासी नितेश कुमार अग्रहरी (कल्लू), बहादुरगंज निवासी सुशील (रिंकू टमाटर), महावीरन गली निवासी राज कुमार केसरवानी (बद्री कचौड़ी), मुट्ठीगंज कार्यालय ज्ञानेन्द्र जायसवाल (वीरू चाय), बादशाही मंडी निवासी आदित्य, झलवा निवासी अश्विनी गुप्ता (अंशु), मालवीय नगर निवासी सुरेश चन्द्र केसरवानी, नैनी निवासी श्रीमती सुमित्रा देवी केसरवानी, जानसेनगंज निवासी रोहित (जूस), मोती महल निवासी संतोष, गुड़मंडी निवासी ऋषि गुप्ता, जीवन ज्योति हॉस्पिटल के सामने श्रीमती मंजू गुप्ता, पत्थरचट्टी रामलीला मैदान के सामने श्रीमती मंजू गुप्ता शामिल रहीं।

इस अवसर पर भाजपा महानगर संयोजक दीप द्विवेदी, मंडल अध्यक्ष मुट्ठीगंज परमानंद वर्मा, चौक मंडल अध्यक्ष सुमित वैश्य, कीडगंज मंडल अध्यक्ष कबीर जायसवाल नैनी मंडल अध्यक्ष रजत दुबे, मीरापुर मंडल अध्यक्ष गया निषाद आदि मौजूद रहे।

अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव, परमार्थ निकेतन-2026 के चौथे दिन चक्रों, आयुर्वेद और नाड़ी ज्ञान को समर्पित

मंत्र भारत संवाददाता

प्रयागराज। परमार्थ निकेतन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव, 2026 के चौथे दिन लगभग 80 देशों से 1500 से अधिक आए प्रतिभागियों और योग जिज्ञासुओं को आज भारत की प्राचीन विधा आयुर्वेद के विषय में विशेषज्ञों से गहन जानकारी प्राप्त हुई। आज का दिन सूर्योदय ध्यान से लेकर सायंकालीन भक्तिमय संगीत तक अत्यंत उत्साह व दिव्यता से युक्त था। पारंपरिक योगिक अभ्यासों, दार्शनिक ज्ञान और समग्र उपचार का एक समृद्ध संगम था।

आज 'विजडम टॉक्स' आध्यात्मिक संगोष्ठी के अन्तर्गत ''आयुर्वेद- समग्रता का संतुलन, समन्वय और योगिक जीवन के माध्यम से स्वास्थ्य।' विषय पर विशेषज्ञों ने जानकारी प्रदान की।

इस सत्र में प्रतिष्ठित आचार्य और विशेषज्ञ डा रामकुमार, डॉ. कृष्णा पंकज नारम और मारिया अलेजांद्रा अवचारियन ने अपने विचार साझा किए, जिसका संचालन पौला तापिया ने किया। चर्चा में जानकारी दी कि आयुर्वेद किस प्रकार प्रकृति के साथ सामंजस्य में जीवन जीने और शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक कल्याण को विकसित करने का एक कालातीत दर्शन है।

परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष, अन्तर्राष्ट्रीय योग महोत्सव के प्रेरणास्रोत पूज्य स्वामी चिदानन्द सरस्वती जी ने कहा कि आयुर्वेद सनातन संस्कृति की एक अमूल्य और जीवंत धरोहर है, जो हमारे जीवन को प्रकृति के साथ संतुलन में जीने की प्रेरणा देती है। 'आयु' अर्थात जीवन और 'वेद' अर्थात ज्ञान, इन दोनों का समन्वय ही आयुर्वेद है। यह केवल रोगों के उपचार की पद्धति नहीं, बल्कि स्वस्थ, संतुलित और जागरूक जीवन जीने की संपूर्ण जीवनशैली है। हमारे ऋषि-मुनियों ने गहन तप, अनुभव और प्रकृति के सूक्ष्म अवलोकन से इस विज्ञान को विकसित किया। आयुर्वेद हमें संदेश देता है कि शुद्ध आहार, संतुलित दिनचर्या, सकारात्मक विचार और प्रकृति के अनुरूप जीवन ही वास्तविक स्वास्थ्य और दीर्घायु का आधार हैं।

डा साध्वी भगवती सरस्वती जी ने कहा कि वर्तमान समय में पूरे विश्व को योग व आयुर्वेद की सबसे अधिक आवश्यकता है। इस समय जब पूरा विश्व तनाव, असंतुलित जीवनशैली और बढ़ती बीमारियों की चुनौती से जूझ रहा है, तब योग और आयुर्वेद की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक महसूस की जा रही है। योग शरीर, मन और आत्मा को संतुलन में लाकर आंतरिक शांति और स्थिरता प्रदान करता है, वहीं आयुर्वेद प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए स्वस्थ और संतुलित जीवन का मार्ग दिखाता है। यह दोनों ही सनातन ज्ञान की अमूल्य देन हैं, जो केवल रोगों के उपचार तक सीमित नहीं, बल्कि जीवन को समग्र रूप से स्वस्थ, जागरूक और संतुलित बनाने की दिशा प्रदान करते हैं।

चौथे दिवस की सुबह माँ गंगा के पावन तट पर सूर्योदय के साथ ही साधकों ने योगाचार्य सुधांशु शर्मा के साथ सनराइज चैंटिंग का आनंद लिया, पूरा गंगा तट मंत्रोच्चार और भक्ति से वातावरण गुंजायमान हो उठा।

योगाचार्य डॉ. इन्दु शर्मा द्वारा क्रिया योग तथा डॉ. रुचि गुलाटी द्वारा प्राणायाम तकनीकों का अभ्यास कराया गया, जिससे प्रतिभागियों ने श्वास और आंतरिक ऊर्जा के साथ गहरा संबंध अनुभव किया।मुंबई से आई प्रतिभागी मित्तल ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा, यह मेरा परमार्थ निकेतन आने का पहला अवसर है। यहाँ आकर नए लोगों से मिलना, आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करना, माँ गंगा के साथ जुड़ना और गंगा आरती का हिस्सा बनना मेरे लिए अत्यंत विशेष अनुभव है।'

मांसपेशी-संरक्षण तकनीक से सफल घुटना प्रत्यारोपण,मरीज अगले दिन से चलने लगा

मंत्र भारत संवाददाता

प्रयागराज। स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय में 60 वर्षीय मरीज के बाएं घुटने का सफल टोटल नी रिप्लेसमेंट (ऊखें) किया गया। यह सर्जरी ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉ. आनंद कुमार की टीम ने आधुनिक सबवास्टस एप्रोच तकनीक से की। मरीज लंबे समय से घुटने के तीव्र दर्द और चलने-फिरने में कठिनाई से परेशान थे। जांच में घुटने के जोड़ में उन्नत स्तर का ऑस्टियोआर्थराइटिस पाया गया, जिसके बाद टोटल नी रिप्लेसमेंट का निर्णय लिया गया।

डॉ. आनंद कुमार ने बताया कि सबवास्टस एप्रोच एक मसल-स्पेरिंग तकनीक है, जिसमें जांघ की मुख्य मांसपेशियों को काटे बिना ऑपरेशन किया जाता है। इससे मरीज को कम दर्द, कम रक्तस्राव और शीघ्र पुनर्वास का लाभ मिलता है। इस तकनीक की खासियत यह है कि मरीज ऑपरेशन के अगले ही दिन सहारे से चलना शुरू कर देता है।

सर्जरी टीम में डॉ. सैफ और डॉ. रंजीत शामिल रहे, जबकि एनेस्थीसिया विभाग से डॉ. नितिन और डॉ. अंकित ने सहयोग दिया। ऑपरेशन थिएटर स्टाफ का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा।

मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रो. डॉ. वी.के. पांडेय ने टीम को बधाई देते हुए कहा कि स्वरूप रानी चिकित्सालय में आधुनिक तकनीकों के माध्यम से मरीजों को बेहतर और सुरक्षित उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है। ऑपरेशन सफल रहा और मरीज की स्थिति स्थिर है। चिकित्सकों के अनुसार, कुछ ही दिनों में मरीज सामान्य गतिविधियों में लौट सकेगा।

इफको में 55वां राष्ट्रीय सुरक्षा अभियान का समापन समारोह सकुशल सम्पन्न

मंत्र भारत संवाददाता

प्रयागराज। इफको फूलपुर इकाई में 55 वां राष्ट्रीय सुरक्षा अभियान का समापन समारोह अग्नि एवं सुरक्षा विभाग में सम्पन्न हुआ। इस वर्ष का विषय उन्नत सुरक्षा के लिए लोगों को संलग्न करें, शिक्षित करे और सशक्त बनाएँ है। महाप्रबंधक (इकाई प्रमुख) पी.के.सिंह ने कहा कि आज का दिन हमें सुरक्षा के महत्तव व जागरूकता की याद दिलाता है। उन्होंने कहा कि दुर्घटना के प्रति सचेत रहे और सुरक्षित कार्य करें, सुरक्षा को कभी भी नजरअंदाज ना करें। सुरक्षा उपकरणों, हेलमेट, सूट व गैजेट का अवश्य प्रयोग करें। फायर अलार्म एवं प्राथमिक सुरक्षा के बारे में जागरूक रहें। सुरक्षा को अपनी आदत एवं अपनी कार्य संस्कृति का हिस्सा बनाये। उन्होंने कहा कि आप सभी लोग संकल्प करें कि सुरक्षा नियमों का पालन करेंगे, नये कर्मचारियों को शिक्षित करेंगे और सुरक्षा को जीवनचर्या का हिस्सा बनायेंगे। महाप्रबंधक तकनीकी रत्नेश कुमार ने कहा कि जानकारी अवश्य तुरंत साझा करें ताकि तय समय में अग्नि एवं सुरक्षा विभाग द्वारा दुर्घटना का निवारण किया जा सके। कार्य निष्पादन मां सुरक्षा मानकों का अवश्य ध्यान रखें। मुख्य प्रबंधक अग्नि एवं सुरक्षा विभाग संजीव कुमार ने अग्नि एवं सुरक्षा विभाग की वार्षिक रिपोर्ट पेश की तथा बताया कि हम 1814 दिन दुर्घटना रहित कार्य करे रहें है जो हमारी उपलब्धि है। दुर्घटना निवारण हेतु 1173 टूल बाक्स इंस्टाल किये गये है। उन्होंने बताया कि अग्नि एवं सुरक्षा विभाग को गत वर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद एवं ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल से अवार्ड प्राप्त हुए है। कार्यक्रम का संचालन विकास कुमार एवं धन्यवाद ज्ञापन अखिलेश निगम ने किया। इस दौरान संयुक्त महाप्रबंधक क्रमशः अरूण कुमार, एस.के. सिंह, ए.के.गुप्ता, डॉ सत्य प्रकाश, आर.पी.यादव, संदीप गोयल,विभागाध्यक्ष मानव संसाधन शम्भू शेखर, इफको ऑफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अनुराग तिवारी व महामंत्री स्वयम् प्रकाश, इफको इम्पलाइज संघ के अध्यक्ष पंकज पाण्डेय व महामंत्री विजय कुमार यादव तथा बड़ी संख्या में इफको कर्मचारी मौजूद रहे। इस दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह के दौरान हुए विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजेताओं एवं विभागों को पुरस्कृत किया गया।

पूर्व विधायक राधेश्याम भारतीय पंचतत्व में विलीन

मंत्र भारत संवाददाता

प्रयागराज। सिराथू के पूर्व विधायक राधेश्याम भारतीय का राजकीय सम्मान के साथ मंगलवार सुबह रसूलाबाद घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। पूर्व विधायक के भतीजे संजय भारतीय ने मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार के समय रसूलाबाद घाट पर भारी भीड़ थी।स्टैनली रोड स्थित इंद्रप्रस्थ कॉलोनी से रसूलाबाद घाट की अंतिम यात्रा के पहले पूर्व विधायक का पार्थिव शरीर को समाजवादी पार्टी के झंडे में लपेटा गया। फूलों का चक्र चढ़ाकर अंतिम श्रद्धांजलि दी। इसके बाद पूर्व विधायक का पार्थिव शरीर रसूलाबाद घाट पहुंचा तो अंतिम संस्कार के पहले गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान सपा व अन्य दलों के नेता के साथ लोगों का हुजूम मौजूद रहा। पूर्व विधायक ने बुधवार को अपने आवास पर 70 वर्ष की आयु में अंतिम सांस ली थी।

स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय में विश्व किडनी दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम

मंत्र भारत संवाददाता

प्रयागराज। स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय में विश्व किडनी दिवस के अवसर पर एक जनजागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर किडनी रोगियों के लिए विशेष डाइट चार्ट का विमोचन प्रधानाचार्य प्रो. डॉ. वी.के. पांडेय एवं एसआईसी डॉ. नीलम सिंह द्वारा किया गया।

कार्यक्रम में किडनी रोगों की बढ़ती समस्या, उनके बचाव, समय पर जांच तथा संतुलित आहार और स्वस्थ जीवनशैली के महत्व पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम का आयोजन नेफ्रोलॉजी विभाग की सहायक आचार्य डॉ. सौम्या गुप्ता द्वारा किया गया तथा इसका नेतृत्व नेफ्रोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉ. अरविंद गुप्ता एवं यूरोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉ. दिलीप चौरसिया ने किया।

इस अवसर पर डॉ. अरविंद गुप्ता ने बताया कि आज के समय में डायबिटीज और उच्च रक्तचाप किडनी रोग के प्रमुख कारण बनते जा रहे हैं। यदि इन बीमारियों को नियंत्रित रखा जाए, पर्याप्त पानी पिया जाए और समय-समय पर किडनी की जांच कराई जाए तो किडनी की गंभीर बीमारियों से काफी हद तक बचाव संभव है। उन्होंने यह भी कहा कि संतुलित आहार और स्वस्थ जीवनशैली किडनी को लंबे समय तक स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

कार्यक्रम में प्लास्टिक सर्जरी विभागाध्यक्ष डॉ. मोहित जैन, डॉ. श्रीश मिश्रा, डॉ. दीपक गुप्ता, डॉ. संतोष मौर्य सहित अन्य संकाय सदस्य, रेजिडेंट चिकित्सक एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

कार्यक्रम का उद्देश्य मरीजों एवं आमजन को किडनी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना तथा संतुलित आहार और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करना रहा।

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर टोरेंट पावर की महिला कर्मचारियों का 'गिव टू गेन' सेवा अभियान

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भिवंडी।अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर टोरेंट पावर लिमिटेड की महिला कर्मचारियों ने समाज के प्रति अपनी संवेदनशीलता और सेवा भावना का परिचय देते हुए 'गिव टू गेन (उग्न टू उेग्ह)' थीम के तहत एक विशेष सामुदायिक सेवा अभियान चलाया। इस पहल के अंतर्गत महिला टोरेंटियनों ने विभिन्न वृद्धाश्रमों और एक बालिका आश्रम का दौरा कर वहां के निवासियों के साथ समय बिताया और उन्हें आत्मीयता व अपनत्व का अनुभव कराया। कार्यक्रम के तहत महिला कर्मचारियों ने कई सामाजिक संस्थानों का दौरा किया, जिनमें वनप्रस्थी आश्रम (आंगांव), मातोश्री वृद्धाश्रम (खडवली), स्वामी शांति प्रकाश वृद्धाश्रम (उल्हासनगर), उपवन ओल्ड एज होम (ठाणे), श्री साईधाम वृद्धाश्रम (खिडकाली) और बालिकाश्रम आंगांव शामिल हैं। इस दौरान आश्रमों में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों और बालिकाओं के साथ संवाद, खेल, संगीत और अन्य मनोरंजक गतिविधियों का आयोजन किया गया। इन गतिविधियों के माध्यम से सभी प्रतिभागियों के बीच एक गर्मजोशी भरा और आनंदमय वातावरण बना, जहाँ बातचीत और सहभागिता के जरिए भावनात्मक जुड़ाव के कई यादगार पल बने। यह पहल 'गिव टू गेन' की भावना को साकार करती है। महिला कर्मचारियों ने अपना समय, साथ और स्नेह देकर जहाँ आश्रम के निवासियों के चेहरों पर मुस्कान लाई, वहीं बदले में उन्हें बुजुर्गों का आशीर्वाद, जीवन के अनुभवों से मिली सीख और समाज के प्रति गहरी संवेदनशीलता भी प्राप्त हुई। साथ ही यह कार्यक्रम महिला कर्मचारियों के व्यक्तित्व विकास और सशक्तिकरण का भी महत्वपूर्ण मंच बना। कार्यक्रम की योजना, समन्वय, संवाद और नेतृत्व जैसे विभिन्न पहलुओं में सक्रिय भागीदारी के माध्यम से प्रतिभागियों को अपनी संगठनात्मक और पारस्परिक कौशल को मजबूत करने का अवसर मिला। आश्रम के निवासियों की उत्साहपूर्ण भागीदारी ने इस आयोजन को विशेष बना दिया। इस पहल ने न केवल अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के महत्व को सार्थक बनाया, बल्कि समाज के साथ संवेदनशील जुड़ाव और मानवीय मूल्यों को भी मजबूत किया।

यशवंतराव चव्हाण जयंती पर भिवंडी निजामपुर मनपा में हुआ अभिवादन कार्यक्रम

भिवंडी। भिवंडी निजामपुर शहर महानगरपालिका मुख्यालय में बुधवार को यशवंतराव चव्हाण की जयंती श्रद्धापूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर महानगरपालिका के अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। कार्यक्रम का आयोजन महाराष्ट्र शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार किया गया। महानगरपालिका मुख्यालय के भूतल पर आयोजित समारोह में अतिरिक्त आयुक्त विठ्ठल डाके ने यशवंतराव चव्हाण के चित्र पर पुष्पहार अर्पित कर उन्हें अभिवादन किया। इस अवसर पर उपायुक्त (आस्थापना) सपना वसावा, सहायक आयुक्त (निवडणूक) नितीन पाटील, महापौर के विशेष कार्य अधिकारी अजित महाडीक तथा समाजकल्याण विभाग प्रमुख मिलींद पळसुले सहित महानगरपालिका के अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे।कार्यक्रम के दौरान उपस्थित अधिकारियों ने यशवंतराव चव्हाण के कार्यों और उनके योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

कानपुर में मौत की ड्राइविंग! रंगदारी ना मिली तो रेस्टोरेंट मालिक को 50 मीटर तक घसीटा, खौफनाक मंजर सीसीटीवी में कैद

लखनऊ **(एजेंसी)**। प्रदेश के कानपुर जिले में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। रंगदारी ना देने पर एक रेस्टोरेंट मालिक के बेटे को कार की खिड़की में फंसाकर बीच सड़क पर करीब 50 मीटर तक घसीटा गया। इस खौफनाक वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है।

वारदात मंगलवार रात करीब 12:15 बजे की है। बर्रा निवासी रंजीत सिंह का रामगोपाल चौराहे पर कृष्णा स्वीट हाउस एंड रेस्टोरेंट है। रंजीत का बेटा आदर्श रात को रेस्टोरेंट बंद कर बाहर खड़ा था, तभी जरौली निवासी याशू कुमार अपनी एसयूवी कार से वहां पहुंचा। आरोपी ने धमकाते हुए कहा कि होली में बहुत कमाई की है, चलो अब मेरी हिस्सेदारी निकालो। जब आदर्श ने पैसे देने से मना किया, तो आरोपी गाली-गलौज और मारपीट पर उतारू हो गया। उसने आदर्श की जेब से पैसे निकालने की कोशिश की और इस छीना-झपटी में उसकी सोने की चेन भी टूट गई। विरोध करने पर आरोपी याशू ने कार के अंदर से ही आदर्श का कॉलर पकड़ लिया और अचानक गाड़ी दौड़ा दी।

निलंबित आईएएस अभिषेक प्रकाश को बड़ी राहत

1 करोड़ रिश्वत मामले में प्राथमिकी रद्द और नौकरी बहाली के आदेश!

लखनऊ **(एजेंसी)**। प्रदेश में सोलर एनर्जी पावर प्लांट से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में निलंबित आईएएस अधिकारी अभिषेक प्रकाश को बड़ी राहत मिली है। दरअसल, उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाईकोर्टने प्राथमिकी रद्द करने के बाद बहाली के आदेश दिए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उनकी बहाली का आदेश 14 मार्च 2026 के बाद से प्रभावी माना जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच द्वारा उनके खिलाफ दाखिल चार्जशीट को रद्द किए जाने के बाद विभागीय स्तर पर उनकी बहाली की तैयारी पूरी कर ली गई है।

आप को बता दें कि उत्तर प्रदेश में सोलर ऊर्जा से जुड़े कल-पुर्जे बनाने वाली कंपनी से एक करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप लगा था। इस मामले को लेकर गोमतीनगर थाने में दर्ज प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। हालांकि इसमें केवल 'सीनियर अफसर' लिखा गया था, लेकिन किसी भी अधिकारी का नाम स्पष्ट रूप से नहीं दिया गया था।

बाद में निकांत जैन की पुलिस कस्टडी रिमांड की सुनवाई के दौरान भ्रष्टाचार अधिनियम की स्पेशल कोर्ट ने आदेश दिया है कि जांच अधिकारी यह बताए कि किस वरिष्ठ अधिकारी ने निकांत जैन का नंबर देकर उससे मिलने को कहा था। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि उस कमीशन में शामिल लोक सेवा अधिकारी का नाम, मिलने वाली रकम और उस रकम के लिए की गई कोशिशों के बारे में भी जांच अधिकारी स्पष्ट बयान दें।

'गौरतलब'है कि कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सोलर एनर्जी पावर प्लांट लगाने वाली कंपनी से मिली शिकायत के बाद अभिषेक प्रकाश को 5 प्रतिशत कमीशन मांगने पर निलंबित कर दिया था। अभिषेक प्रकाश का जन्म 21 नवंबर 1982 को बिहार में हुआ था। उन्होंने बीटेक के बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एमए किया। वे इन्वेस्ट यूपी के सीईओ और उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास विभाग के सचिव रह चुके हैं। इसके अलावा, अभिषेक प्रकाश ने 1 नवंबर 2021 से 6 जून 2022 तक लखनऊ के जिलाधिकारी के तौर पर भी काम किया।

पद्मनगर-मार्कंडेयनगर में शिव मंदिर निर्माण के लिए भूमिपूजन, भक्तिमय माहौल में गूंजे 'हर हर महादेव' के जयकारे

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भिवंडी। शहर के पद्मनगर-मार्कंडेयनगर क्षेत्र में प्रस्तावित शिव मंदिर के निर्माण के लिए गुरुवार को धार्मिक उत्साह के साथ भूमिपूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्थानीय नगरसेवक सुमित पाटील के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक शामिल हुए। वेदपंडितों के मंत्रोच्चार के बीच विशेष पूजा-अर्चना की गई और 'हर हर महादेव' के जयघोष से पूरा परिसर भक्तिमय वातावरण से गूंज उठा।

कार्यक्रम में वेदपंडितों के मार्गदर्शन में शास्त्रोक्त विधि से भूमिपूजन संपन्न कराया गया। इस अवसर पर क्यातम राजू, कोम्पेल्ली चंद्रमौळी, क्यातम प्रसाद, आडेपू भिक्षापती, गड्डम देवय्या, पसुनुरी वड्कोश्वर, कट्टगाणी शंकर, आमंच वेंकटेश और सुधामणी आनंद सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सभी ने भगवान शिव की पूजा-अभिषेक कर मंदिर निर्माण कार्य सफलतापूर्वक पूरा होने की कामना की।

स्थानीय नागरिकों के अनुसार, जिस स्थान पर मंदिर का निर्माण प्रस्तावित है वहां पहले एक पुरानी कुआं थी। पास के नाले का गंदा पानी उसमें मिल जाने से कुआं पूरी तरह खराब हो गया था और आसपास दुर्गंध फैलने लगी थी। नगरसेवक सुमित पाटील ने कई बार कुएं की सफाई कराने का प्रयास किया, लेकिन समस्या पूरी तरह हल नहीं हो सकी। इससे आसपास के लोगों को काफी परेशानी और स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था।

इसी समस्या के समाधान के लिए स्थानीय लोगों ने उस स्थान पर मंदिर निर्माण की मांग रखी। नागरिकों की मांग को ध्यान में रखते हुए नगरसेवक सुमित पाटील ने अपने निजी खर्च से लगभग 28 गज भूमि पर भव्य शिव मंदिर बनवाने का आश्वासन दिया था। उसी के तहत गुरुवार को मंदिर निर्माण के लिए विधिवत भूमिपूजन किया गया।

स्थानीय लोगों ने विश्वास जताया कि मंदिर बनने के बाद इस क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक शांति और संतोष मिलेगा तथा इलाके में धार्मिक वातावरण का निर्माण होगा। नागरिकों ने समाजहित में इस पहल के लिए सुमित पाटील की सराहना करते हुए कहा कि जनप्रतिनिधि का असली कर्तव्य जनता की समस्याओं का समाधान करना और समाज के विकास के लिए आगे आना है।

कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिला, युवा और वरिष्ठ नागरिक उपस्थित रहे। सभी ने कामना की कि शिव मंदिर का निर्माण जल्द पूरा हो और श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के द्वार खोले जाएं।

बेड पर न्यूड पड़ी थी दुनिया की मशहूर स्टार काइली जेनर, सिर्फ स्टॉकिंग्स पहनकर बिस्तर पर हुईं बेपर्दा, तस्वीरें देख फैंस के छूटे पसीने!

रियलिटी टीवी स्टार और बिजनेस टाइकून काइली जेनर एक बार फिर अपनी बोल्डनेस और बेबाकी को लेकर सुर्खियों में हैं। 'वैनिटी फेयर' मैगजीन के स्प्रिंग 2026 इश्यू के लिए काइली ने एक बेहद साहसी फोटोशूट कराया है, जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। प्रसिद्ध फोटोग्राफर मर्ट अलास द्वारा खींची गई इन तस्वीरों में काइली सिर्फ स्टॉकिंग्स पहने बिस्तर पर टॉपलेस पोज देती नजर आ रही हैं। इस फोटोशूट के लिए काइली ने दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड्स जैसे डोल्से एंड गब्बाना, हर्मीस और शनेल के कपड़ों का चुनाव किया। हालांकि, सबसे ज्यादा चर्चा उनके बेडरूम शॉट्स की हो रही है, जहाँ उन्होंने स्किम्स अंडरवियर और स्टॉकिंग्स के साथ एक ड्रामैटिक और ग्लैमरस लुक अपनाया है।

फोटोशूट में जेनर पॉल सिंक्लेयर के स्टाइल किए हुए कई हाई-फैशन लुक्स में हैं, जिसमें डोल्से एंड गब्बाना, हर्मीस और शनेल के पीस शामिल हैं। सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली तस्वीरों में बेडरूम के इंटिमेट शॉट्स हैं, जिसमें वह स्किम्स अंडरवियर और स्टॉकिंग्स पहने हुए टॉपलेस दिख रही हैं, जो एडिटोरियल के ड्रामैटिक और ग्लैमरस टोन को और बढ़ा देता है। मैगज़ीन फीचर एक इंटरव्यू के साथ आता है जिसमें जेनर लोगों की नजरों में बड़े होने और कम उम्र से ही फेम पाने के बारे में बताती हैं। रियलिटी टीवी पर बड़े होने के बारे में काइली जेनर ने क्या कहा? इंटरव्यू में, जेनर ने कीपिंग अप विद द कार्दशियन के ज़रिए मिली अपनी शुरुआती शोहरत के बारे में बताया, जो पहली बार 2007 में एयर हुआ था। उन्होंने कहा कि उनके परिवार को इस बात का बहुत कम अंदाज़ा था कि यह शो दुनिया भर में इतना अटेंशन दिलाएगा।

जेनर ने कहा, 'मुझे नहीं लगता कि हममें से किसी को भी शुरू में पता था कि हम किस चीज़ में पड़ रहे हैं,' उन्होंने याद किया कि कैसे वह पहली बार नौ साल की उम्र में टेलीविज़न पर आई थीं।

आज उस अनुभव के बारे में सोचते हुए, जेनर ने अपने बच्चों के साथ इसके अंतर पर ध्यान दिया। उन्होंने कहा, 'मैं 9 साल की थी। अब मेरी एक बेटी है जो 8 साल की होने वाली है, इसलिए उसे देखना और वह कितनी छोटी है, यह देखना बहुत अजीब है,' उन्होंने यह मानते हुए कि ज़्यादातर बचपन की तुलना में उनकी परवरिश कितनी अलग थी।

जेनर अब दो बच्चों की माँ हैं -- बेटी स्टॉर्मी, आठ साल की, और बेटा आयर, चार साल का। इंटरव्यू के दौरान, उन्होंने माँ बनने को अपनी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बताया और कहा कि वह भविष्य में अपने परिवार को बढ़ाना चाहती हैं। उन्होंने यह भी बताया कि आने वाले साल अपने बिज़नेस के साथ ट्रैवलिंग और बच्चों की परवरिश में लगने वाले समय को बैलेंस करने पर फोकस करेंगे। उन्होंने कहा, 'अपने 20 के आखिरी सालों में, मैं सिर्फ खुद पर, अपने बिज़नेस, अपने काम, अपने बच्चों के साथ ट्रैवलिंग और अपने बच्चों के साथ एन्जॉय करने पर फोकस करना चाहती हूं।'

सीट टूटी, फर्श गला और चली गई जान आगरा में स्कूल बस बनी मासूम का काल

लखनऊ **(एजेंसी)**। प्रदेश के आगरा में स्कूल प्रबंधन की जानलेवा लापरवाही ने एक हंसते-खेलते परिवार की खुशियां उजाड़ दीं। भागूपुर स्थित आरबीएस इंटर कॉलेज की एक जर्जर बस चलते-चलते मौत का जाल बन गई। बस का फर्श इतना सड़ा-गला था कि वह अचानक टूट गया और कक्षा 1 की छात्रा नैना चलती गाड़ी से सड़क पर गिर गई, जिसके बाद बस का भारी पहिया उसे कुचलता हुआ निकल गया।

नगला लाले निवासी ब्रह्मजीत की 9 वर्षीय बेटी नैना अपनी बड़ी बहन के साथ बुधवार को स्कूल से घर लौट रही थी। चश्मदीदों के मुताबिक, नैना अपनी सीट पर बैठी थी, तभी अचानक सीट के नीचे लगी लोहे की गली हुई चद्दर (फर्श) भरभरा कर टूट गई। नैना संभल भी नहीं पाई और सीधे सड़क पर जा गिरी। पलक झपकते ही बस का पिछला पहिया उसके ऊपर चढ़ गया। बस में सवार अन्य बच्चों के शोर मचाने पर जब तक ड्राइवर ने गाड़ी रोकी, तब तक नैना की सांसें थम चुकी थीं।

परिजनों और ग्रामीणों का आरोप है कि जिस बस में मासूमों को ढोया जा रहा था, वह पूरी तरह खटारा थी। बस की सीटें टूटी हुई थीं, खिड़कियां लटक रही थीं और सबसे खतरनाक उसका फर्श था, जो जंग लगकर गल चुका था। आरोप है कि बस के पास न तो वैध फिटनेस सर्टिफिकेट था और न ही सुरक्षा के कोई मानक पूरे किए गए थे।

अस्पताल में जब डॉक्टरों ने नैना को मृत घोषित किया, तो कोहराम मच गया। अपनी लाडली का शव देखकर मां और दादी बार-बार बेहोश हो रही थीं। पिता ब्रह्मजीत ने नम आंखों से स्कूल प्रबंधन पर सीधा आरोप लगाया कि उनकी लापरवाही ने उनकी बेटी की 'हत्या' की है। आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम करने की कोशिश की और दोषियों को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की।

एत्मादपुर पुलिस ने बस को जब्त कर लिया है और ड्राइवर से पूछताछ जारी है। पुलिस का कहना है कि स्कूल प्रशासन को नोटिस जारी किया गया है और जांच रिपोर्ट के आधार पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अयोध्या दौरे से पहले एक्शन में मुख्यमंत्री योगी, अधिकारियों को दिए कड़े निर्देश

लखनऊ **(एजेंसी)**। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को अयोध्या के सीएफसी सभागार में राष्ट्रपति की प्रस्तावित अयोध्या यात्रा के संबंध में समीक्षा बैठक की। अयोध्या के जिला मजिस्ट्रेट निखिल टिकाराम फुंडे ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 मार्च को अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन करेंगी। बुधवार को पत्रकारों से बात करते हुए जिला मजिस्ट्रेट फुंडे ने कहा कि राष्ट्रपति की यात्रा की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। योगी ने कहा कि राष्ट्रपति 19 मार्च को जिले में आ रही हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। आयुक्त, एडीजी और डीआईजी ने सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। सभी को निर्देश मिल चुके हैं। सभी विभाग उसी के अनुसार काम कर रहे हैं और 19 तारीख का कार्यक्रम सुचारू रूप से आयोजित किया जाएगा। 19 तारीख हिंदू नव वर्ष का पहला दिन भी है। उन्होंने कहा कि इस बात को ध्यान में रखते हुए, हम यहां लोगों के लिए सुगम दर्शन सुनिश्चित करेंगे। हम यह सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं कि यहां आने वाले सभी श्रद्धालु दर्शन कर सकें। उस दिन मंदिर के दर्शन एक घंटा पहले शुरू होंगे और देर रात तक जारी रहेंगे... आम श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा से बचाने के लिए, कोई वीवीआईपी पास या कोई विशेष पास जारी नहीं किया जाएगा। दर्शन निर्बाध रूप से जारी रहेंगे। राष्ट्रपति और हमारे गणमान्य व्यक्तियों के आगमन और पूजा के समय ही कुछ क्षणों के लिए दर्शन बंद किए जाएंगे। बाकी सभी अनुष्ठान जारी रहेंगे। इस बीच, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को नई दिल्ली में 'जल महोत्सव 2026' को संबोधित किया। इस अवसर पर बोलते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि भारत में जल केवल एक बुनियादी सुविधा नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति, परंपराओं, आजीविका और सामुदायिक जीवन से जुड़ा हुआ है।

लापता बच्चों की रिपोर्ट : पश्चिम बंगाल बच्चों के लिए सबसे असुरक्षित? एनसीआरबी रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। भारत भर में लापता बच्चों की बढ़ती संख्या एक गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की नवीनतम 'लापता बच्चे' रिपोर्ट के अनुसार, 1 जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2026 के बीच कुल 33, 577 बच्चे लापता हुए। हालांकि अधिकारियों ने इनमें से कई बच्चों का पता लगा लिया है, फिर भी 7, 777 बच्चे लापता हैं, जो इस समस्या की भयावहता को उजागर करता है।

देशभर में बच्चों के लापता होने के आंकड़े चिंताजनक हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की 'मिसिंग चिल्ड्रन' की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 1 जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2026 के बीच देश में कुल 33, 577 बच्चे गायब हुए। इनमें से 7, 777 बच्चे अब तक नहीं मिले। रिपोर्ट में बताया गया है कि सबसे ज्यादा 19, 145 बच्चे पश्चिम बंगाल में लापता हुए। इनमें से 15, 465 बच्चों को ढूंढ लिया गया, जबकि 3, 680 बच्चे अब भी नहीं मिले। मध्यप्रदेश में 4.256 बच्चे लापता हुए। इनमें से 1, 059 बच्चों का अब तक पता नहीं चल पाया। बच्चों के लापत्ता होने के मामलों में हरियाणा देश में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। 1 जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2026 तक हरियाणा में 2209 बच्चे लापता हुए, लेकिन इनमें से 353 का कोई सुराग नहीं लग पाया। हरियाणा में लापता बच्चों की संख्या पंजाब, हिमाचल और चंडीगढ़ से कई गुना ज्यादा है। रिपोर्ट के अनुसार, पश्चिम बंगाल में लापता बच्चों की संख्या सबसे अधिक रही, इस अवधि के दौरान 19, 145 मामले दर्ज किए गए। इनमें से 15, 465 बच्चों का पता लगाया जा चुका है, जबकि 3, 680 बच्चे अभी भी लापता हैं। केस 1 सहेली के घर गई, फिर नहीं लौटी अम्बाला की 14 वर्षीय लड़की 8 जनवरी को सहेली के घर जाने की बात कहकर निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। बस स्टैंड की सीसीटीवी फुटेज मिली, जिसमें वह जाते दिखी, पर आगे

केस 2 नाराज होकर घर से निकली, अब तक लापता-अम्बाला कैंट में 5 फरवरी को लड़की परिवार से नाराजा होकर घर से निकल गई और वापस नहीं लौटी। गुमशुदगी का केस है। पिता शहर में पर्चे बांटकर लोगों से

बाल अधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि आंकड़े लापता बच्चों का पता लगाने के लिए मजबूत निगरानी प्रणालियों, पुलिस की त्वरित कार्रवाई और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता को उजागर करते हैं। अधिकारियों ने जनता से संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने और लापता बच्चों का पता लगाने और उन्हें उनके परिवारों से मिलाने में मदद करने वाली जानकारी प्रदान करने का आग्रह करना जारी रखा है।

टी20 वर्ल्ड कप से पहले पिता के निधन का दर्द झेल रहा क्रिकेटर बोला- उनके साथ रहना ज्यादा जरूरी था

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। भारतीय टीम और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के विकेटकीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा ने हाल ही में एक भावुक खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि टी20 विश्व कप 2026 से ठीक पहले उनके पिता का निधन हो गया था। चयनकर्ताओं ने टूर्नामेंट के लिए उनकी जगह ईशान किशन को टीम में शामिल किया था। जितेश ने कहा कि शुरुआत में टीम से बाहर होने का दुख जरूर हुआ, लेकिन बाद में उन्हें महसूस हुआ कि उस समय उनके पिता को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी।

समाचार एजेंसी से बातचीत में जितेश शर्मा ने बताया कि जब उन्हें टी20 वर्ल्ड कप टीम में जगह नहीं मिलने की खबर मिली तो वह निराश हो गए थे। हालांकि कुछ ही दिनों बाद उनके जीवन में एक और बड़ा झटका आया, जब उनके पिता की तबीयत अचानक खराब हो गई। 1 फरवरी को उनके पिता का निधन हो गया। जितेश ने बताया कि वह अपने पिता के अंतिम दिनों में लगभग एक हफ्ते तक उनके साथ रहे और उनकी देखभाल की।

जितेश शर्मा ने कहा कि बाद में उन्हें महसूस हुआ कि उस समय वर्ल्ड कप से ज्यादा महत्वपूर्ण अपने पिता के साथ रहना था।उन्होंने कहा कि अब उन्हें इस बात का कोई पछतावा नहीं है कि वह टीम में शामिल नहीं हो पाए। उनके अनुसार भगवान का शुक्र है कि वह अपने पिता के अंतिम दिनों में उनके साथ रह सके और उनकी सेवा कर सके।

जितेश शर्मा ने बताया कि उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप के सभी मुकाबले घर से ही देखे। भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया और लगातार दूसरी बार ट्रॉफी जीतकर इतिहास रच दिया। जितेश ने कहा कि घर से मैच देखना एक अलग और ज्यादा तनाव भरा अनुभव था, लेकिन उन्हें टीम इंडिया की सफलता पर बेहद गर्व है।

जितेश शर्मा का कहना है कि भारतीय टीम की जीत खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत और स्पष्ट विजन का नतीजा है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों ने कप्तान, कोच और टीम मैनेजमेंट की रणनीति को बेहतरीन तरीके से मैदान पर लागू किया। यही वजह रही कि टीम ने टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया।

टी20 वर्ल्ड कप के बाद अब जितेश शर्मा की नजर इंडियन प्रीमियर लीग 2026 पर है। वह पिछले सीजन की चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ओर से इस बार भी मैदान में उतरेंगे। जितेश ने बताया कि टीम ने हाल ही में एक छोटा प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया था, जिसमें सभी खिलाड़ियों ने अपनी तैयारी को मजबूत किया।

आईपीएल 2026 : वॉटसन और रसेल जैसे कोच मिलना हमारे लिए सौभाग्य : रमनदीप सिंह

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। आईपीएल 2026 से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स के ऑलराउंडर रमनदीप सिंह ने टीम के कोचिंग स्टाफ को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि दिग्गज ऑलराउंडर शेन वॉटसन और आंद्रे रसेल जैसे खिलाड़ियों के साथ काम करना उनके लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं है। रमनदीप का मानना है कि इन दिग्गजों से सीखकर वह अपने खेल को और बेहतर बनाना चाहते हैं।

आईपीएल 2026 में शेन वॉटसन केकेआर के सहायक कोच के रूप में जुड़े हैं, जबकि आंद्रे रसेल टीम में पावर कोच की भूमिका निभा रहे हैं। इस पर रमनदीप सिंह ने कहा कि इन दोनों दिग्गजों का डगआउट में होना टीम के लिए बड़ी बात है। रमनदीप ने कहा, 'डगआउट में वॉटसन और रसेल जैसे खिलाड़ी होना हमारे लिए आशीर्वाद है। मैं उनसे जितना हो सके उतना सीखना चाहता हूं और उम्मीद है कि मैं भी टीम के लिए मैच जिताने वाले पल में वैसा ही प्रदर्शन कर सकूं।'

28 वर्षीय रमनदीप सिंह साल 2024 में केकेआर से जुड़े थे और उसी साल टीम ने अपना तीसरा आईपीएल खिताब जीता था। इसके बाद से रमनदीप ने टीम के लिए उपयोगी प्रदर्शन किया है। उन्होंने अब तक आईपीएल में 172 रन बनाए हैं, 167.9 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है और 6 विकेट भी अपने नाम किए हैं।

रमनदीप सिंह ने घरेलू क्रिकेट में भी शानदार प्रदर्शन किया। 2025 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उन्होंने पंजाब के लिए खेलते हुए बेहतरीन ऑलराउंड प्रदर्शन किया। इस टूर्नामेंट में उन्होंने 209 रन बनाए, 195 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की और 10 मैचों में 9 विकेट हासिल किए। रमनदीप ने कहा कि इस सीजन में उनका पूरा ध्यान मैच की स्थिति को समझकर खेलने पर है। उन्होंने कहा, 'मैं हर बार बल्लेबाजी करने जाते समय संभावित परिस्थितियों को समझने की कोशिश करता हूं। साथ ही पिच कैसे बदल रही है, उसे देखकर सही शॉट खेलने पर काम कर रहा हूं।'

रमनदीप सिंह ने कहा कि अगर मौका मिला तो वह गेंदबाजी से भी टीम के लिए योगदान देना चाहेंगे। उन्होंने कहा, 'अगर मौका मिला तो मैं गेंदबाजी में भी अच्छा प्रदर्शन करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे अंदर एक बेहतर ऑलराउंडर बनने की क्षमता है। मैं मैदान पर अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा और उम्मीद है कि अच्छे परिणाम मिलेंगे।'

एयरलाइंस को बड़ी राहत!

इंडिगो-एयर इंडिया के खिलाफ 'बाजार वर्चस्व' के दुरुपयोग की शिकायत खारिज, सीसीआई ने दी क्लीन चिट

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। भारतीय विमानन क्षेत्र की दो सबसे बड़ी कंपनियों, इंडिगो और एयर इंडिया, को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) से बड़ी राहत मिली है। आयोग ने उन शिकायतों को सिरे से खारिज कर दिया है जिनमें इन एयरलाइंस पर बाजार में अपनी मजबूत स्थिति का दुरुपयोग करने और टिकट कैंसिलेशन (रद्दीकरण) के नाम पर यात्रियों से अत्यधिक शुल्क वसूलने के आरोप लगाए गए थे। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि दोनों एयरलाइन कंपनियां टिकट रद्द करने पर अत्यधिक शुल्क लेती हैं और सेवाओं की बिक्री में मनमाने नियम एवं कीमतें लागू करती हैं। शिकायत में कहा गया था कि इंटरग्लोब एविएशन की एयरलाइन इंडिगो के पास घरेलू विमानन बाजार में 65 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी है जबकि एयर इंडिया की हिस्सेदारी करीब 27 प्रतिशत है। शिकायत के मुताबिक, दोनों कंपनियों की संयुक्त हिस्सेदारी लगभग 90 प्रतिशत होने के कारण बाजार में वर्चस्व और प्रतिस्पर्धा-रोधी व्यवहार से जुड़ी आशंकाएं जताई गई थी।

हालांकि, मामले की जांच के बाद आयोग ने कहा कि उपलब्ध जानकारी से प्रतिस्पर्धा कानून के प्रावधानों के उल्लंघन का प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता है। सीसीआई ने कहा कि टिकट के पैसे लौटाने और टिकट रद्द करने की व्यवस्था मौजूद है और यात्रियों के पास अधिक रिफंड की पात्रता वाली टिकट श्रेणी चुनने का विकल्प भी होता है। इसके अलावा रिफंड और रद्दीकरण से जुड़े नियम यात्रियों को पहले से बताए जाते हैं और सभी उपभोक्ताओं पर समान रूप से लागू होते हैं। आयोग ने आदेश में कहा कि उपलब्ध तथ्यों के आधार पर प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा तीन और चार के उल्लंघन का कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता, इसलिए शिकायत को धारा 26(2) के तहत बंद किया जाता है। धारा तीन और चार क्रमशः प्रतिस्पर्धा-विरोधी समझौतों और बाजार में दबदबे के दुरुपयोग से संबंधित हैं।

आईसीसी ने 103.8 करोड़ की प्राइज मनी का किया बंटवारा

भारत के साथ सभी टीमों को मिली इतनी धनराशि

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। आईसीसी ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए अपनी प्राइज मनी में इजाफा किया है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल द्वारा इस टूर्नामेंट की प्राइज मनी के विभाजन की विस्तृत जानकारी शेयर की गई है। इस जानकारी के मुताबिक तकरीबन 103.8 करोड़ रुपये यानी 11.25 मिलियन यूएस डॉलर की इनामी राशि का बंटवारा किया गया है। आईसीसी ने सभी 20 टीमों को कितनी राशि दी हमारी इस रिपोर्ट में देखें। विजेता भारतीय टीम को सबसे ज्यादा तकरीबन 2.6 मिलियन यूएस डॉलर यानी 24.3 करोड़ रुपये मिले हैं। वहीं भारत के अलावा रनर अप न्यूजीलैंड, सेमीफाइनल में हारने वाली साउथ अफ्रीका की टीम को भी 11 मिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा की राशि मिली है। दरअसल, ये राशि प्रत्येक टीम के राउंड वाइज जगह बनाने और प्रत्येक मैच जीतने के हिसाब से बांटी गई है। वहीं प्रत्येक मैच जीतने के लिए एक टीम को 26 लाख रुपये मिले हैं। वहीं जो टीम एक भी मैच नहीं जीता पाईं और उन्होंने टूर्नामेंट में हिस्सा लिया, जैसे कनाडा, नामीबिया और ओमान, उन्हें भी 2.25 लाख यूएस डॉलर यानी तकरीबन 2 करोड़ से ज्यादा रुपये मिले हैं। इसका मतलब है कि कोई भी टीम टी20 वर्ल्ड कप से खाली हाथ नहीं लौटी है।

शुभमन गिल को क्रिकेटर ऑफ द ईयर, राहुल द्रविड़ को मिलेगा बीसीसीआई लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। पूर्व भारतीय कोच राहुल द्रविड़ को बीसीसीआई द्वारा 15 मार्च को दिल्ली में आयोजित सालाना नमन अवॉर्ड्स में कर्नल सीके नायडू लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से सम्मानित किया जाएगा जबकि भारत के टेस्ट व वनडे कप्तान शुभमन गिल को क्रिकेटर ऑफ द ईयर के सम्मान से सम्मानित किया जाएगा।

इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक भारत की पूर्व महिला कप्तान मिताली राज को भी लाइफटाइम अवॉर्ड देने पर विचार किया जा रहा है। जबकि मुंबई के आयुष म्हात्रे को उनके प्रदर्शन के लिए घरेलू लिमिटेड ओवर क्रिकेट में बेस्ट ऑलराउंडर के लिए अमरनाथ अवॉर्ड से सम्मानित किया जाएगा। बता दें कि, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली और वीवीएस लक्ष्मण के साथ भारत की मशहूर बिग फोर बैटिंग लाइन-अप का हिस्सा थे। द्रविड़ ने इस सभी स्टार बल्लेबाजों की टीम में मौजूदगी के बावजूद अपना खास स्थान बनाया था और उन्हें अपनी पीढ़ी के बेस्ट टेस्ट बल्लेबाजों में से एक माना जाता है।

राहुल द्रविड़ ने वनडे प्रारूप में भी 10 हजार से ज्यादा रन बनाए थे और टेस्ट क्रिकेट में वो काफी असरदार रहे थे और उन्होंने घर में साथ ही विदेशी धरती पर भी खूब बन बनाए थे। साल 2012 में क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद उन्होंने शुरू में कमेंट्री किया और फिर कोचिंग में आ गए। बाद में उन्होंने इंडिया अंडर 19 टीम की कमान संभी और शुभमन गिल और पृथ्वी शॉ जैसे खिलाड़ियों वाली टीम को साल 2018 में अंडर 19 वर्ल्ड कप का खिताब दिलाया। इस दौरान उन्होंने इंडिया ए टीम के साथ मिलकर भी काम किया।

राहुल द्रविड़ को इसके बाद साल 2021 में रवि शास्त्री की जगह भारतीय सीनियर टीम का हेड कोच बनाया गया और उनके कार्यक्रम में भारत ने 2023 वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बनाई, लेकिन टीम चैंपियन बनने से चूक गई। वहीं साल 2024 में भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज में टी20 वर्ल्ड कप टाइटल अपने नाम किया।

पाकिस्तान की बांग्लादेश के खिलाफ हार से भड़के बासित अली, पीसीबी पर उठाए गंभीर सवाल

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बुरा हाल हुआ था, उसके बाद बांग्लादेश दौरे पर भी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की दिशा और दशा दोनों नहीं सुधर पा रही है। बांग्लादेश के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में पाकिस्तान की टीम 31वें ओवर में ही 114 रन पर सिमट गई। बांग्लादेश ने 15.1 ओवर में ही 2 विकेट गंवाकर मैच जीता लिया। इसके बाद पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर बासित अली बुरी तरह भड़क गए और उन्होंने पाकिस्तान टीम और पीसीबी को लताड़ा है।

बासित अली ने पाकिस्तान क्रिकेट मैनेजमेंट पर सवाल उठाए हैं और उनकी प्लानिंग को भी घेरे में लिया है। उन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान की पहले 10 ओवर में धीमे खेलने और सधी शुरुआत करने की स्ट्रेटजी पर सवाल उठाए। वहीं उन्होंने एकसाथ कई सारे युवा खिलाड़ियों को

उतारने को लेकर भी सवाल उठाए।

बासित अली ने पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट को लताड़ते हुए कहा कि, सबसे पहले गोली मार दो उस आदमी को जिन्होंने बोला पॉवरप्ले के 10 ओवर में कम से कम 60 रन बनाने का कहा। उन्होंने कभी खुद ग्राउंड पर क्रिकेट नहीं खेला। वह बस एक कागज का टुकड़ा पकड़ा देते हैं। क्या उन्हें दिखता नहीं है कि यहां कंडीशन कैसी हैं? क्या उन्हेंये नहीं पता कि भारत तक बांग्लादेश में हारकर गया है?

बासित ने आगे युवा खिलाड़ियों को खिलाने पर कहा कि, इस डिबेट को खत्म करना होगा कि युवाओं को समय की जरूरत है। दुनियाभर के क्रिकेट में जब युवा मैदान पर उतरते हैं तो वह तैयार होते हैं। वह अपनी छाप छोड़ते हैं। हमारे खिलाड़ियों को समझना होगा कि ये लोकल क्लब ग्राउंड नहीं है। ये एक इंटरनेशनल टेस्ट वेन्यू है। टीम के दो खिलाड़ी बराबर कह रहे थे कि वह मध्यक्रम के बेस्ट बल्लेबाज हैं आपने देख लिया उन्होंने आज क्या किया।

पाकिस्तान की बल्लेबाजी बांग्लादेश के खिलाफ पहले मैच में बुरी तरह फ्लाप रही। मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आघा, दोनों अनुभवी खिलाड़ियों ने निराश किया। पाकिस्तान की तरफ से इस मैच में चार खिलाड़ियों ने डेब्यू किया। पाकिस्तान की टीम का स्कोर 82 रन पर 9 विकेट था और आखिरी में फहीम अशरफ ने 37 रन की बदौलत स्कोर 114 तक पहुंचा। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 8 विकेट से करारी शिकस्त दी और सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली।

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में हिस्सा नहीं लेगा ईरान, सुरक्षा का दिया हवाला

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। ईरान के स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने ऐलान किया है कि, उनका देश फीफा वर्ल्ड कप 2026 में हिस्सा नहीं लेगा। उन्होंने अपने लीडर की यूएस द्वारा हत्या और हाल की गलत हरकतों का जिक्र किया। ईरानी फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट ने भी यही बात दोहराई है। हालांकि, फीफा के प्रेसिडेंट ने पहले कहा था कि ईरानी टीम का यूएस में स्वागत किया जाएगा, जो टूर्नामेंट को होस्ट कर रहा है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, ईरान के स्पोर्ट्स मिनिस्टर अहमद दोन्यामाली ने बुधवार को कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की अमेरिका द्वारा हत्या के बाद उनका देश 2026 फीफा वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं ले सकता। रिपोर्ट के मुताबित अहमद दोन्यामाली ने बुधवार को सरकारी टेलीविजन से कहा कि, ये देखते हुए कि इस भ्रष्ट सरकार ने हमारे लीडर की हत्या की है, हम किसी भी हालात में वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं ले सकते।

दोन्यामाली ने कहा कि, हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं हैं और असल में हिस्सा लेने के लिए ऐसे हालात मौजूद नहीं हैं। ईरान के खिलाफ उन्होंने जो गलत काम किए हैं उन्हें देखते हुए उन्होंने आठ या 9 महीनों में हम पर दो जंग थोपी हैं। और हमारे हजारों लोगों को मारा और शहीद किया।

पश्चिम रेलवे
वडोदरा मंडल

नए/प्रतिस्थापन के रूप में लिफ्ट सहित प्रस्तावित फुट ओवर ब्रिज (FOB) का निर्माण

निविदा सूचना संख्या: DRM-BRC 201 वर्ष 2025-26 भारत के राष्ट्रपति की ओर से डिविजनल रेलवे मैनेजर (WA/C), वेस्टर्न रेलवे, प्रतापनगर, वडोदरा-390004 द्वारा नीचे दिए गए कामों के लिए सीलबंद ई-निविदा मंगाए गए हैं। **क्रमांक 1. टेंडर नंबर और काम का नाम: DRM BRC 201 of 2025-26.** वडोदरा मंडल:कोसंबा, पानौली एवं हथुरण स्टेशनों पर नए/प्रतिस्थापन के रूप में लिफ्ट सहित प्रस्तावित फुट ओवर ब्रिज (FOB) का निर्माण। **काम की अनुमानित लागत (रुपये में) :** 12,13,28,539.90 **जमा की जाने वाली बिड सिक्योरिटी (रुपये में):** 7,56,700.00 **निविदा प्रस्तुत करने तथा निविदा खोलने की तिथि एवं समय:** निविदा दिनांक 30.03.2026 को 15.00 बजे से पहले प्रस्तुत की जानी है तथा उसी तिथि को 15.30 बजे खोली जानी है। **वेबसाइट विवरण तथा उस स्थान के निर्देश जहां पूर्ण विवरण देखा जा सकता है तथा निविदा प्रपत्र खरीदा जा सकता है कार्यालय का पता: वेबसाइट: www.ireps.gov.in.** मंडल रेल प्रबंधक (डब्ल्यूए/सी) पश्चिम रेलवे, प्रतापनगर, वडोदरा - 390 004. BRC 391

हमें लाइक करें: facebook.com/WesternRly

पश्चिम रेलवे – रतलाम मंडल

ई-निविदा सूचना

निविदा संख्या: SnT_RTM_26_01_SIGNAL, दिनांक: 10.03.2026. कार्य का नाम: नीमच स्टेशन: नीमच - बड़ी सादरी नई लाइन परियोजना की कनेक्टिविटी के लिए आंतरिक कार्य करना से संबंधित सिग्नलिंग सामग्री की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और चालू करना। **कार्य की अनुमानित लागत:** रु 1,55,47,815.44. **बयाना राशि:** रु 2,27,700/-. **निविदा बंद करने का समय एवं दिनांक:** दिनांक 06.04.2026 समय 15:00 बजे तक। **निविदा खुलने का समय एवं दिनांक:** दिनांक 06.04.2026 समय 15:30 बजे के बाद। **कार्य पूरा करने की अवधि:** 12 माह। **निविदा अनुभाग कार्यालय प्रभारी और बोली खोलने का स्थान:** सीनियर डीएसटीई रतलाम, डीआरएम कार्यालय रतलाम म.प्र. निविदा सिर्फ ऑनलाइन E-निविदा पोर्टल **www.ireps.gov.in** पर देखा व जमा किया जा सकता है। DE/6/1/505

हमें लाइक करें: facebook.com/WesternRly

कृतिका कामरा और गौरव कपूर ने रचाई शादी! लाल साड़ी में दुल्हन की सादगी ने जीता फैंस का दिल

टेलीविजन और फिल्म जगत की मशहूर अभिनेत्री कृतिका कामरा और जाने-माने होस्ट व अभिनेता गौरव कपूर आखिरकार हमेशा के लिए एक-दूसरे के हो गए हैं। बुधवार, 11 मार्च को इस पावर कपल ने एक प्राइवेट सिविल वेडिंग में शादी के पेपर्स साइन किए। ग्लैमर की चमक-धमक से दूर, दोनों ने अपने घर की छत (टेरेस) पर परिवार और बेहद करीबी दोस्तों की मौजूदगी में सादगी से अपना मिलन सेलिब्रेट किया। सोशल मीडिया पर शादी के 'साइनिंग मोमेंट' की पहली अंदरूनी तस्वीर वायरल हो रही है, जिसे मशहूर फोटोग्राफर जोसेफ राधिक ने कैप्चर किया है। 37 साल की कृतिका कामरा एक सिंपल लाल साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही थीं, जिसे उन्होंने चोकर, लेयर्ड नेकलेस और इयररिंग्स के साथ और

भी खूबसूरत बनाया। 44 साल के गौरव कपूर ने बेज रंग का बंदगला कुर्ता सेट पहना था। उनकी शादी की तस्वीरें और इनसाइड फोटो फोटोग्राफर जोसेफ राधिक ने शेयर कीं। शादी के बाद, नए शादीशुदा जोड़े ने एक साथ ड्रीमी फोटो खिंचवाईं। उनके साइनिंग मोमेंट का एक पल भी पोस्ट किया गया।

हालांकि कृतिका और गौरव की शादी बहुत छोटी थी, लेकिन एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स की दुनिया के कुछ जाने-माने चेहरे इस सेरेमनी का हिस्सा थे। शादी के मेहमानों में फरहान अख्तर, सोहा अली खान, श्रेया धनवंतरी, पूजा गौर, अन्या सिंह, अंगद बेदी, वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह और हेज़ल, और कई दूसरे लोग शामिल थे।

अपनी शादी के एक दिन बाद, गुरुवार, 12 मार्च को, कृतिका और गौरव दोस्तों और साथ काम करने वालों के लिए एक रिसेप्शन होस्ट करने वाले हैं। 'द पार्टी, आफ्टर' टाइटल वाली इस पार्टी में फिल्म और क्रिकेट दोनों सर्कल से मेहमानों के आने की उम्मीद है, जो दोनों इंडस्ट्रीज़ के साथ कपल के करीबी रिश्तों को दिखाता है।

इस बीच, उनके रिसेप्शन इनवाइट की एक झलक सोशल मीडिया पर शेयर हो रही है। नोट में लिखा है: 'हम अपनी शादी आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहेंगे। आराम से। बिना किसी जल्दबाजी के। जल्दी आइए। जब तक रात हो, रुकिए।' इस इनवाइट पर नए शादीशुदा जोड़े ने साइन किया था, जिससे सेलिब्रेशन में एक पर्सनल टच आ गया।

रुपए में बड़ी गिरावट, डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। भारतीय करेंसी में गिरावट का सिलसिला जारी है। गुरुवार को कारोबार के दौरान रुपया 35 पैसे कमजोर होकर डॉलर के मुकाबले 92.36 के स्तर तक पहुंच गया, जो अब तक का सर्वकालिक निचला स्तर है। पश्चिमी एशिया में जारी संघर्ष के थमने के कोई संकेत न दिखने के मद्देजनर विदेशी पूंजी की निकासी, वैश्विक कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और डॉलर के मजबूत रुख से घरेलू मुद्रा दबाव में है।

विदेशी मुद्रा कारोबारियों के अनुसार, घरेलू शेयर बाजारों में सत्र की कमजोर शुरुआत ने स्थानीय मुद्रा पर और दबाव डाला।रुपया बुधवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 92.01 पर बंद हुआ था। इस बीच, छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.24 प्रतिशत की बढ़त के साथ 99.47 पर रहा। घरेलू शेयर बाजारों में सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 992.53 अंक फिसलकर 75, 871.18 अंक पर जबकि निफ्टी 310.55 अंक टूटकर 23, 556.30 अंक पर आ गया। अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड का भाव 9.94 प्रतिशत चढ़कर 101.12 डॉलर प्रति बैरल हो गया। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) बुधवार को बिवकाल रहे थे और उन्होंने 6, 267.31 करोड़ रुपए के शेयर बेचे।

बृहन्मुंबई महानगरपालिका

मुख्य अभियंता (मल-जल संचालन) विभाग
क्रमांक : ई.ई.एम./सीवर/8133 सिटी-1 दिनांक : 11 मार्च 2026

ई-निविदा सूचना

बृहन्मुंबई महानगरपालिका के आयुक्त द्वारा निम्नलिखित ऑनलाइन निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा की प्रति महा-टेंडर पोर्टल (https://mahatenders.gov.in/nicgep/app) के ई-प्रोक्योरमेंट अनुभाग से डाउनलोड की जा सकती है।

अ.क्र	निविदा का विषय	निविदा आईडी	ईएमडी (रू)	निविदा शुल्क	निविदा जमा करने की अंतिम तिथि
1.	ए.ई. (पम्पिंग) दक्षिण के अंतर्गत मझगांव पम्पिंग स्टेशन पर प्लेटफॉर्म का निर्माण, आपूर्ति और स्थापना।	2026_MCGM_1285928_1	13,500/-	3,630/- + 18% जीएसटी	20.03.2026 को 16:00 बजे तक।

वेबसाइट :https://portal.mcgm.gov.in
https://mahatenders.gov.in/nicgep/app
ई-मेल : eemechscity1.so@mcgm.gov.in

(सतीश ए. शिंदे)
कार्यकारी अभियंता यांत्रिक (मल-जल)
सिटी-1

पीआरओ/3264/विज्ञा./2025-26

भोजन से पूर्व एवं शौच के बाद साबुन से हाथ स्वच्छ धोएं।

मेघालय में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ सड़कों पर उतरा लोगों का हुजूम, सरकार पर साधा निशाना

शिलांग । मेघालय की राजधानी शिलांग में अवैध घुसपैठ के मुद्दे को लेकर व्यापक जनाक्रोश देखने को मिल रहा है। हम आपको बता दें कि मोटफ्रान क्षेत्र में आयोजित एक विशाल जनसभा में विभिन्न सामाजिक संगठनों और छात्र समूहों ने बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ जोरदार आवाज उठाई। इस सभा का आयोजन मेघालय सामाजिक संगठन महासंघ ने किया था, जिसमें गारो पहाड़ क्षेत्र के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त की गई।

सभा के दौरान प्रदर्शनकारियों ने 'गो बैक बांग्लादेशी' जैसे नारे लगाए और आरोप लगाया कि अवैध घुसपैठ की समस्या ने राज्य के जनजातीय समाज, भूमि अधिकार और राजनीतिक अधिकारों को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। वक्ताओं ने कहा कि यदि समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो स्थानीय समुदायों की पहचान और अस्तित्व पर खतरा मंडरा सकता है।

इस जनसभा में गारो पहाड़ से कई सामाजिक संगठनों और नेताओं ने भाग लिया। बड़ी संख्या में छात्र भी कार्यक्रम में शामिल हुए। सभा में वक्ताओं ने राज्य सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि सरकार जनजातीय समुदायों के हितों की रक्षा करने में असफल रही है।

नानग्रीमगिमिन अचिक डोल के अध्यक्ष डेविड मराक ने कहा कि अवैध घुसपैठ के कारण गारो पहाड़ क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक संतुलन बिगड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कई बाहरी लोग आजीविका के अवसरों का लाभ उठा रहे हैं और कुछ मामलों में बिना उचित

निगरानी के मकान बनाकर बेनामी गतिविधियां भी चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह स्थिति पिछले नेताओं की लापरवाही का परिणाम है जिन्होंने संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधानों की रक्षा नहीं की।

वहीं मेघालय सामाजिक संगठन महासंघ के अध्यक्ष राय कुपर सिनरेम ने गारो पहाड़ के लोगों के प्रति एकजुटता जताते हुए कहा कि हिन्युट्रेप समुदाय अचिक समाज के साथ खड़ा है। उन्होंने आरोप लगाया कि गारो पहाड़ स्वायत्त जिला परिषद चुनाव को स्थगित करने का निर्णय जनता को भ्रमित करने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि सरकार को पता है कि जनता आगामी चुनाव में सत्ताधारी दल के पक्ष में मतदान नहीं करेगी।

सिनरेम ने सरकार से अवैध घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें वापस भेजने की मांग भी की। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि इस समस्या का स्थायी समाधान किया जाए और राज्य की भूमि तथा संसाधनों की रक्षा की जाए।

इसके अलावा, हिटो के अध्यक्ष डोनबोक खार ने कहा कि चुनाव स्थगित होना गारो पहाड़ के लोगों की एक उपलब्धि है क्योंकि इससे उनकी आवाज को बल मिला है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वह मिलकर अपनी भूमि और अधिकारों की रक्षा करें।

सभा में खनम के कार्यकारी अध्यक्ष थामस पासाह ने कहा कि वर्तमान परिस्थिति यह संकेत देती है कि जनजातीय समुदायों की सुरक्षा के लिए कानूनी प्रावधानों को और मजबूत करने की आवश्यकता है। उन्होंने असम और मेघालय स्वायत्त जिला परिषद नियम 1951 के कुछ प्रावधानों में संशोधन की मांग की ताकि जनजातीय क्षेत्रों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

वहीं जैन्तिया राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष सामबोर्मी लिंगदो ने भी सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की दिशा किसी और के हाथों में प्रतीत होती है, जबकि शासन की बागडोर स्वयं सरकार के हाथ में होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि चुनाव के समय अवैध घुसपैठिये स्थानीय समुदायों को चुनौती दे रहे हैं तो यह प्रशासनिक व्यवस्था की विफलता को दर्शाता है। सभा के दौरान प्रदर्शनकारियों ने कई तख्तियां भी उठाई थीं जिन पर जनजातीय अधिकारों की रक्षा और अवैध घुसपैठ रोकने की मांग लिखी हुई थी। खराब मौसम के बावजूद सैकड़ों लोग इस जनसभा में शामिल हुए। हम आपको बता दें कि सभा से पहले सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी और मोटफ्रान तथा आसपास के इलाकों में पुलिस बल तैनात किया गया था। कई दुकानदारों ने भी एहतियात के तौर पर अपनी दुकानें बंद रखीं। हम आपको बता दें कि गारो पहाड़ क्षेत्र में हाल के दिनों में तनाव और हिंसा की घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें पुलिस की गोलीबारी में दो लोगों की मौत होने की खबर भी सामने आई है।

एलपीजी संकट पर विपक्ष का हंगामा,कंगना रनौत बोलीं- ये जनता को गुमराह करने की साजिश है

नई दिल्ली। भाजपा सांसद कंगना रनौत ने गुरुवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कथित एलपीजी संकट से देश को उसी तरह निकालेंगे जैसे उन्होंने कोविड महामारी के दौरान निकाला था। रनौत ने एलपीजी सिलेंडर संकट पर विपक्ष के विरोध प्रदर्शन की आलोचना करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा की और वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत की प्रगति पर प्रकाश डाला। कंगना रनौत ने कहा कि पूरी दुनिया प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व देख रही है। दुनिया भर में महंगाई बढ़ रही है, लेकिन हमारे देश में हर दिन नई परियोजनाएं शुरू हो रही हैं। एलपीजी की स्थिति को लेकर पूर्ण आश्वासन दिया गया है, लेकिन वे (विपक्ष) दहशत फैलाने और जनता को गुमराह करने के लिए यह (विरोध प्रदर्शन) कर रहे हैं। जनता को प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा रखना चाहिए, जो कोविड महामारी के दौरान की तरह ही नेतृत्व करेंगे।

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने गुरुवार को संसद परिसर में एलपीजी गैस सिलेंडरों की देशव्यापी कमी की खबरों के विरोध में अपना प्रदर्शन जारी रखा। भारत गठबंधन के नेताओं ने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बीच एलपीजी की कथित कमी पर चर्चा की मांग की है। एलपीजी की कमी का संकट देश के कई हिस्सों में भी व्याप्त है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने गुरुवार को संसद में द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) की कमी की खबरों पर चर्चा करने का आग्रह किया और इस बात पर जोर दिया कि संसद जनता को आश्वस्त करने और ऐसे महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करने का मंच है।

ऐसे मुद्दों पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। सरकार को इसकी जानकारी दी जानी चाहिए। आप जानते हैं कि एलपीजी सिलेंडर के लिए कितनी लंबी लाइनें लगती हैं... कुछ रेस्तरां ने कहा है कि उनके पास खाना पकाने के लिए गैस नहीं है, वे चाय तो दे सकते हैं, लेकिन डोसा नहीं। क्या देश में अभी यही स्थिति है? आप जानते हैं कि कीमतें बढ़ गई हैं। यह एक ऐसा मंच है जहां हम इन सभी मुद्दों को जनता के सामने रख सकते हैं। हम बस इतना चाहते हैं कि इस पर चर्चा हो और सरकार जनता को आश्वासन दे। ऐसा नहीं हो सकता कि वे मनमानी से सरकार चलाएं।

बिहार भर्ती बोर्ड की बड़ी लापरवाही, सालों बाद मिले एडमिट कार्ड पर कुत्ते की तस्वीर

पटना **(एजेंसी)**। सार्वजनिक परीक्षाओं के संचालन में संदिग्ध लापरवाही की एक चौंकाने वाली घटना में, बिहार के रोहतास जिले में एक भर्ती परीक्षा के लिए जारी किए गए एडमिट कार्ड पर कथित तौर पर उसकी तस्वीर के बजाय कुत्ते की तस्वीर लगी हुई है। उम्मीदवार, रितेश कुमार ने 2022 में जिला एवं सत्र न्यायालय में चपरासी के पदों की अधिसूचना जारी होने के बाद परीक्षा के लिए आवेदन किया था। हालांकि, भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड लगभग चार साल की लंबी देरी के बाद हाल ही में जारी किया गया है।

कुमार के अनुसार, जब उन्होंने 15 मार्च को होने वाली प्रारंभिक परीक्षा के लिए अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किया, तो वे यह देखकर हैरान रह गए कि एडमिट कार्ड पर लगी तस्वीर एक गोल्डन रिट्रीवर कुत्ते की थी। नौकरी के इच्छुक उम्मीदवार ने कहा कि आवेदन जमा करते समय उन्होंने अपनी सही तस्वीर अपलोड की थी और अपने दावे को साबित करने के लिए उन्होंने पावती पर्ची की एक प्रति भी प्रस्तुत की। कुमार ने कहा कि इस कथित त्रुटि के कारण उनके इलाके में उनका मज़ाक उड़ाया जा रहा है। उन्होंने यह भी दावा किया कि उन्होंने संबंधित भर्ती बोर्ड में कई शिकायतें दर्ज कराई हैं और इस गलती को सुधारने का अनुरोध किया है। हालांकि, उन्होंने कहा कि परीक्षा की तारीख नजदीक आने के बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उम्मीदवार ने अधिकारियों से आग्रह किया है कि वे इस त्रुटि को तुरंत सुधारें ताकि वे बिना किसी बाधा के परीक्षा में शामिल हो सकें।

जम्मू में फारूक अब्दुल्ला पर गोली चलने से जम्मू-कश्मीर में कानून व्यवस्था की स्थिति पर उठे सवाल

श्रीनगर। जम्मू में बुधवार रात एक शादी समारोह में बंदूकधारी के हमले में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला और जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी बाल-बाल बच गए। यह घटना उस समय हुई जब अब्दुल्ला, उपमुख्यमंत्री चौधरी और मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर असलम वानी शहर के बाहरी इलाके में स्थित ग्रेटर कैलाश क्षेत्र के समारोह स्थल से निकल रहे थे। आरोपी की पहचान कमल सिंह जामवाल के रूप में हुई है, जो पुरानी मंडी का निवासी है। वह पिस्तौल लेकर अब्दुल्ला के पीछे पहुंचा और गोली चला दी। हालांकि जम्मू-कश्मीर पुलिस की सुरक्षा शाखा के दो अधिकारियों ने उसे काबू कर लिया। उपमुख्यमंत्री चौधरी ने इस घटना को 'सुरक्षा में चूक' बताया, जबकि पुलिस ने कहा कि विस्तृत जांच जारी है।

अधिकारियों ने बताया कि जामवाल की उम्र 70 वर्ष से अधिक है और हमले के वक्त वह नशे की हालत में था। उन्होंने बताया कि सतर्क कर्मियों द्वारा उसका हथियार छीने जाने और जमीन पर गिराए जाने से पहले उसने एक गोली चलाई। अधिकारियों ने यह भी बताया कि गोलीबारी में कोई घायल नहीं हुआ। उधर, हमले पर नाराजगी व्यक्त करते हुए जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा, 'अल्लाह मेहरबान है। मेरे पिता बाल-बाल बच गए।' उन्होंने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि फिलहाल विवरण अस्पष्ट हैं, लेकिन जो ज्ञात है वह यह है कि एक व्यक्ति भरी हुई पिस्तौल के साथ 'बिल्कुल करीब' आकर गोली चलाने में कामयाब हो गया। मुख्यमंत्री ने कहा, ''अंदरुनी घेरे के सुरक्षा दस्ते ने हमले के प्रयास को नाकाम कर दिया। इस समय जवाबों से ज्यादा सवाल हैं, जिनमें यह भी शामिल है कि ज़ेड प्लस श्रेणी के साथ एनएसजी सुरक्षा प्राप्त पूर्व मुख्यमंत्री के इतने करीब कोई व्यक्ति कैसे पहुंच गया।''

बताया जा रहा है कि फारुक अब्दुल्ला और सुरिंदर चौधरी पार्टी नेता बी.एस. चौहान को उनके बेटे की शादी पर बधाई देने आए थे और वे कार्यक्रम स्थल पर एक घंटे से अधिक समय तक मौजूद रहे। उपमुख्यमंत्री ने घटना पर चिंता व्यक्त करते हुए पत्रकारों से कहा कि आपको सुरक्षाकर्मियों और पुलिस से

पूछना चाहिए कि इतनी बड़ी चूक कैसे हुई।

दूसरी ओर, जम्मू शहर के दक्षिण क्षेत्र के पुलिस अधीक्षक अजय शर्मा ने बताया कि विवाह समारोह में लाइसेंस प्राप्त हथियार से गोली चलने की घटना हुई थी। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। प्रारंभिक जांच में किसी प्रकार के आतंकवादी कोण की पुष्टि नहीं हुई है। हम आपको बता दें कि इस घटना के बाद एक वीडियो भी तेजी से प्रसारित हो रहा है जिसमें आरोपी खुद को 63 वर्ष का बताता हुआ नजर आता है। वीडियो में वह दावा करता है कि वह पिछले बीस वर्ष से फारूक अब्दुल्ला को मारने की योजना बना रहा था और यह उसका निजी एजेंडा था। हालांकि पुलिस ने इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है और जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होने की बात कही है।

दूसरी ओर, राजनीतिक और सामाजिक नेताओं ने भी इस घटना की कड़ी निंदा की है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने आज राज्यसभा में यह मामला उठाते हुए जम्मू-कश्मीर में कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाये। वहीं कश्मीर के प्रमुख धार्मिक नेता मीरवाइज उमर फारूक ने इस घटना को चिंताजनक बताते हुए कहा कि किसी वरिष्ठ नेता पर इस तरह का हमला बेहद निंदनीय है और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद लोन ने भी इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि यह कायरतापूर्ण कृत्य है और सौभाग्य की बात है कि सभी नेता सुरक्षित हैं। वहीं पीडीपी के विधायक वहीद पर्रा ने इसे बेहद चौंकाने वाली और दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताया और कहा कि वरिष्ठ नेता के खिलाफ हिंसा किसी भी हालत में स्वीकार नहीं की जा सकती।

नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा रुहुल्लाह मेहदी ने भी कहा कि इस प्रकार की हिंसक घटनाएं लोकतंत्र के लिए गंभीर चिंता का विषय हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा भी की जा रही है ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोका जा सके। हालांकि यह घटना एक बार फिर वीआईपी सुरक्षा व्यवस्था और सार्वजनिक कार्यक्रमों में सुरक्षा प्रबंधों पर गंभीर सवाल खड़े करती है।

बलूचिस्तान में पाकिस्तान का क्रूर ऑपरेशन सख्त कर्फ्यू में भूख से तड़प रहे बच्चे!

खुजदार **(एजेंसी)**। बलूचिस्तान के कुछ हिस्सों में निवासियों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि अधिकारियों ने खुजदार जिले के ज़हरी में सख्त पाबंदियां लगा दी हैं और सुरक्षा बलों ने सुराब क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अभियान चलाया है, जिससे स्थानीय समुदायों पर मानवीय प्रभाव को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। बलूच यकजेहती कमेटी (बीवाईसी) ने मौजूदा स्थिति की निंदा करते हुए ज़हरी में लंबे समय से जारी कर्फ्यू को नागरिकों के लिए बेहद चिंताजनक बताया है। बलूचिस्तान पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, बीवाईसी ने एक बयान में कहा कि शहर लगातार चार दिनों से पूरी तरह से बंद है, जिससे रमजान के महीने में निवासियों का जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। बलूचिस्तान पोस्ट के मुताबिक, कमेटी ने कहा कि कर्फ्यू ने आम परिवारों के लिए गंभीर मुश्किलें खड़ी कर दी हैं, जिन्हें भोजन और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है। बीवाईसी ने

दावा किया कि कई घरों में कमी का सामना करना पड़ रहा है और बाजार और आपूर्ति तक पहुंच प्रतिबंधित होने के कारण बच्चे भूखे मर रहे हैं।

स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच भी प्रभावित हुई है। बीवाईसी ने बताया कि सड़क बंद होने और आवागमन पर प्रतिबंध के कारण तत्काल चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता वाले मरीज अस्पतालों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं।

समूह ने आगे कहा कि नाकाबंदी ने न केवल ज़हरी कस्बे को अलग-थलग कर दिया है, बल्कि आसपास के गांवों का भी संपर्क काट दिया है, जिससे हजारों लोग फंसे हुए हैं और एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने में असमर्थ हैं।

इसी बीच, संगठन ने आरोप लगाया कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने सुराब के लघर और आसपास के इलाकों में बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान चलाया।

बड़ी संख्या में सैनिक सैन्य वाहनों के साथ इलाके में दाखिल हुए और घर-घर तलाशी शुरू कर दी। इन छापों के दौरान, कई घरों में जबरन घुसपैठ की गई। बीवाईसी ने दावा किया कि कुछ मामलों में दरवाजे और खिड़कियां तोड़ दी गईं, जबकि तलाशी के दौरान घरेलू सामान और फर्नीचर को नुकसान पहुंचाया गया। बलूचिस्तान पोस्ट द्वारा प्रकाशित खबर के अनुसार, समूह ने यह भी आरोप लगाया कि अभियानों के दौरान महिलाओं और बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। इन घटनाक्रमों ने निवासियों की चिंताओं को और बढ़ा दिया है, जो पहले से ही विस्तारित कर्फ्यू के कारण उत्पन्न कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। बलूचिस्तान कोर ने स्थिति को नागरिक आबादी को प्रभावित करने वाला एक गंभीर मानवीय मुद्दा बताया है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव पर भड़का ईरान अन्यायपूर्ण बताकर दी स्थायी दाग लगने की चेतावनी

न्यूयॉर्क **(एजेंसी)**। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के स्थायी प्रतिनिधि ने सुरक्षा परिषद द्वारा इस्लामी गणराज्य के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने के फैसले पर औपचारिक रूप से खेद व्यक्त किया है। सुरक्षा परिषद के सत्र में बोलते हुए, अमीर-सईद इरावानी ने इस प्रस्ताव को अन्यायपूर्ण और गैरकानूनी' करार दिया। उन्होंने तर्क दिया कि प्रस्ताव का पारित होना सुरक्षा परिषद की विश्वसनीयता को गंभीर झटका है और विश्व निकाय के इतिहास पर एक अमिट दाग है। प्रतिनिधि ने दावा किया कि यह कदम 'सुरक्षा परिषद के जनादेश का घोर दुरुपयोग है, जिसका उद्देश्य 'कुछ सदस्यों के राजनीतिक एजेंडे' को पूरा करना है। उन्होंने आगे कहा कि यह प्रस्ताव जमीनी हकीकतों को तोड़-मरोड़ कर पेश करता है और मौजूदा क्षेत्रीय संकट के मूल कारणों को संबोधित करने में विफल रहता है।

अपने कड़े शब्दों वाले संबोधन में इरावानी ने इस प्रस्ताव की 'पक्षपातपूर्ण और राजनीतिक रूप से प्रेरित' प्रकृति की निंदा की। उन्होंने आरोप लगाया कि यह 'पीड़ित और हमलावर की भूमिकाओं को उलट देता है' और तर्क दिया कि अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया 'दोनों शासनों को और अधिक अपराध करने के लिए प्रोत्साहित करती है। मिशन के आधिकारिक बयानों में इस बात पर ज़ोर दिया गया कि तेहरान परिषद के फैसले को स्वीकार नहीं करेगा। इरावानी ने इस कार्रवाई को 'संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतरराष्ट्रीय कानून के विपरीत' बताया और कहा कि यह 'आक्रामकता के कृत्यों के निर्धारण को नियंत्रित करने वाले स्थापित सिद्धांतों की पूरी तरह से अवहेलना करती है। ईरानी राजनयिक ने परिषद के यूरोपीय सदस्यों की भी कड़ी आलोचना की। उन्होंने दावा किया कि प्रस्ताव के लिए उनका समर्थन यह साबित करता है कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतरराष्ट्रीय कानून की रक्षा करने के उनके दावे खोखले वादे मात्र हैं। इरावानी ने कहा, 'उनका पाखंडी और गैर-जिम्मेदाराना आचरण एक बार फिर यह दर्शाता है कि अंतरराष्ट्रीय कानून के प्रति उनकी घोषित प्रतिबद्धता पर राजनीतिक विचार हावी हैं।' उन्होंने आगे आरोप लगाया कि ये राष्ट्र स्वतंत्र रूप से कार्य करने के बजाय केवल 'वाशिंगटन से मिले राजनीतिक निर्देशों का पालन' कर रहे हैं। राजनयिक दस्तावेजों के अनुसार, ईरानी दूत ने कुछ विशिष्ट सदस्यों पर अमेरिका और इज़राइल की कार्रवाइयों को अनदेखा करते हुए 'ईरान को दोषी ठहराने का एक निंदनीय और स्पष्ट प्रयास' करने का आरोप लगाया। उन्होंने विशेष रूप से 'मीनाब शहर में 170 स्कूली छात्राओं के नरसंहार' का उल्लेख अनदेखी की गई क्रूरताओं के उदाहरण के रूप में किया।

चीन के खिलाफ तिब्बती महिलाओं का जोरदार विरोध, विद्रोह दिवस पर गूंजे आजादी के नारे

बीजिंग **(एजेंसी)**। तिब्बती राष्ट्रीय महिला विद्रोह के 67वें दिवस के उपलक्ष्य में, तिब्बती महिला संघ ने गुरुवार को चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया। इस अवसर पर, बौद्ध भिक्षुणियों और छात्राओं सहित सैकड़ों निर्वासित तिब्बती महिलाएं एकत्र हुईं।

यह आयोजन उस दिन की याद में मनाया जा रहा है जब तिब्बत के तीनों प्रांतों की तिब्बती महिलाओं ने, तिब्बत के इतिहास में पहली बार, एकजुट होकर 1959 में तिब्बत पर कब्जा करने वाली क्रूर चीनी सैन्य बलों के खिलाफ आवाज उठाई थी। इस तरह के आयोजन युवा पीढ़ी को यह दिखाने के लिए हैं कि संघर्ष का क्या अर्थ है और स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की क्या महत्वपूर्ण भूमिका है, जो एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गया है। निर्वासित तिब्बती संसद के सदस्य यूडोन औकात्सांग ने एएनआई को बताया हम यहां तिब्बती महिला विद्रोह के 67वें दिवस के उपलक्ष्य में उपस्थित हैं। यह एक ऐतिहासिक क्षण है क्योंकि हजारों महिलाओं ने चीनी क्रूरता के खिलाफ विद्रोह किया और चीन को तिब्बत छोड़ने के लिए कहा। दरअसल, पहला विरोध प्रदर्शन 10 मार्च को हुआ था, जब वे नोरबुलिंगका के बाहर एकत्रित हुईं

ईरान युद्ध से अमेरिका को अरबों का झटका, बढ़ते तेल के दाम के दबाव में राष्ट्रपति ट्रंप ने दिए बड़े संकेत

वाशिंगटन **(एजेंसी)**। अमेरिकी खुफिया सूत्रों ने संकेत दिया कि ईरान का नेतृत्व अभी भी काफी हद तक बरकरार है और दो सप्ताह से चल रहे निरंतर अमेरिकी और इजरायली युद्ध के बाद भी उसके पतन का कोई खतरा नहीं है। कई खुफिया रिपोर्टों में एक समान विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है कि शासन के पतन का कोई खतरा नहीं है और वह ईरानी जनता पर अपना नियंत्रण बनाए हुए है। नवीनतम रिपोर्ट पिछले कुछ दिनों में पूरी हुई है।

तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर बढ़ते राजनीतिक दबाव के बावजूद, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने संकेत दिया है कि वे 2003 के बाद से सबसे बड़े अमेरिकी सैन्य अभियान को 'जल्द ही' समाप्त कर देंगे। लेकिन अगर ईरान के कट्टरपंथी नेता अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखते हैं तो युद्ध का कोई स्वीकार्य अंत खोजना मुश्किल हो सकता है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट ने 28 फरवरी को, अमेरिकी और इजरायली हमलों के पहले दिन, सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या के बावजूद ईरान के धार्मिक नेतृत्व की एकजुटता को भी रेखांकित किया। दूसरी ओर, इजरायली अधिकारियों ने बंद कमरे में हुई चर्चाओं में स्वीकार किया कि इस बात की कोई निश्चितता नहीं है कि युद्ध से धार्मिक सरकार का पतन हो जाएगा।

रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया कि जमीनी स्थिति अस्थिर है और ईरान के भीतर की परिस्थितियां बदल सकती हैं।

इस बीच, बुधवार को ईरान ने दुनिया के सबसे व्यस्त अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को निशाना बनाया और वाणिज्यिक जहाजों पर हमला किया। अमेरिका और इज़राइल के हमलों से तेहरान हिल गया, वहीं संयुक्त राष्ट्र की सबसे शक्तिशाली संस्था ने वैश्विक तेल आपूर्ति को खतरे में डालने वाले खाड़ी पड़ोसी देशों पर ईरान के हमलों को रोकने की मांग की। ये ताजा हमले ईरान के उस अभियान में एक और मोड़ थे, जिसका उद्देश्य वैश्विक अर्थव्यवस्था को इतना नुकसान पहुंचाना था कि अमेरिका और इज़राइल पर 12 दिन पहले शुरू हुए युद्ध को समाप्त करने का दबाव बन सके। लेकिन संघर्ष के शांत होने के कोई संकेत नहीं थे। पेंटागन के अनुसार, ईरान के साथ युद्ध के पहले सप्ताह में अमेरिका को 11.3 अरब अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ। पेंटागन ने इस सप्ताह की शुरुआत में कांग्रेस को एक ब्रीफिंग में यह अनुमान प्रस्तुत किया था। स्थिति से परिचित एक व्यक्ति ने नाम न छापने की शर्त पर निजी बैठक के बारे में बताया। सेना ने युद्ध के पहले सप्ताहांत में अकेले गोला-बारूद पर 5 अरब अमेरिकी डॉलर खर्च करने की सूचना दी। दोनों पक्ष अपनी-अपनी जगह पर डटे हुए हैं, इस उम्मीद में कि संघर्ष के कारण व्यापार मार्ग बाधित हो रहे हैं।

Facebook: https://www.facebook.com/profile.phpid=100063787346044 Twitter: https://twitter.com/mantrabharatt=8tJONQ7H-h6EKqqap2tVMw&s=08 Mobile No: 7007837917

मंत्र भारत : R.N.I. MAHHIN/ 2016/65841 स्वात्वाधिकारी राकेश शर्मा के लिए राकेश शर्मा द्वारा AIS Printing solution प्लॉट नं0-A- 544 TTC इंडस्ट्रियल एरिया एमआईडीसी माहपे-नवी मुंबई, थाने 400709 से मुद्रित एवं शाप.नं. 36, द्वितीय तल, प्लाट -490.1. जाम मील बिल्डिंग, डॉ बाबा साहेब अम्बेकर रोड, लाल बाग परेल, मुम्बई-400012प्रकाशित एवं सम्पादित । कार्यालय : शाप.नं. 36, द्वितीय तल, प्लाट -490.1. जाम मील बिल्डिंग, डॉ बाबा साहेब अम्बेकर रोड, लाल बाग परेल, मुम्बई-400012 । फोन : 022-24706563 । कार्यकारी सम्पादक- योगेन्द्र चौधरी
E-Mail : editormantrabharat@gmail.com mantrabharatmumbai@gmail.com । सम्पादक : विनोद आर शर्मा, मोबाइल : 7007837917 । समूह सम्पादक : डॉ दयानन्द तिवारी। वैधानिक सूचना : मंत्र भारत से संबंधित समस्त विवाद निपटारे के लिए मंत्र प्रधान कार्यालय क्षेत्र प्रयागराज/ इलाहाबाद न्यायालय ही होगा। प्रधान कार्यालयः 80ए मेंहदौरी, तेलियरगंज, प्रयागराज-211004 (नोटः कानूनी पत्र व्यवहार का पता प्रधान कार्यालय ही होगा।)